

6 | संपादकीय जलसता | 23 जनवरी, 2026

कल्पमेधा

नई दिल्ली

लोगों को सच्चा लोकतंत्र और स्वराज कभी भी हिंसा और असत्य का रास्ता अपनाने से प्राप्त नहीं हो सकता।

- लाल बहादुर शास्त्री

त्रासद हादसा

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए हादसे में जिस तरह दस जवानों की जान चली गई, वह दुर्गम इलाके में तैनात सुरक्षा बलों के सामने मौजूद बहुस्तरीय जोखिम का ही उदाहरण है। गौरतलब है कि गुरुवार को डोडा में सेना के एक बुलेटप्रूफ वाहन में सवार फौजी लगभग नौ हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे। इस बीच खन्नी टाप के पास वाहन सड़क से फिसल कर दो सौ फुट गहरी खाई में जा गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वाहन और उसमें सवार लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दस जवानों की मौत के अलावा ग्यारह अन्य जवान बुरी तरह घायल भी हुए। जाहिर है, आतंकवाद का सामना करने के क्रम में जानलेवा खतरों और हमलों का सामना करने के अलावा इस घटना से वहां डचूटी के लिए तैनात सुरक्षा बलों के सामने एक अतिरिक्त चुनौती का पता चलता है।

यह इलाका अपनी बेहद मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता रहा है और वहां सुरक्षा बलों के जवानों के सामने हमेशा ही जोखिम की स्थिति बनी रहती है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच आतंकवादियों का सामना करना पहले ही एक बड़ी चुनौती रही है। उसमें जब सुरक्षा कारणों से ही सड़कों पर सफर के क्रम में हुए हादसे में जवानों की मौत हो जाती है, तो यह वाहन चलाने में हुई मामूली चूक के खतरनाक नतीजों के साथ-साथ दुर्गम इलाकों में मौजूद रास्तों के बेहद असुरक्षित होने का भी सबूत है। सवाल है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से अतिसंवेदनशील इलाकों में सड़कों को इस हालत में कैसे छोड़ा गया है कि किसी वाहन के खाई में गिरने के बाद उसमें सवार लोगों के जिंदा बचने की गुंजाइश बेहद कम होती है। अफसोस की बात यह है कि उस समूचे क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सामने मौजूद अलग-अलग जोखिम के समांतर बचाव के मोर्चे पर शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। वरना हादसे और जोखिम के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील जगहों पर सड़कों के किनारे मजबूत सुरक्षा घेरा या पैराफिट लगाने भर से पहाड़ी इलाकों में होने वाले हादसों में जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों के दुर्घटना का शिकार होने और जवानों की मौत या उनके घायल होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। वाहन पर से चालक का नियंत्रण खोना एक कारण हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में संकरी और घुमावदार सड़कों के तीखे मोड़ पर फिसलकर का खतरा बना रहता है। ताजा घटना में जिस खन्नी टाप पर सेना का वाहन हादसे का शिकार हुआ, उस तरह की जगहों पर ऊंचाई और कंकड़-मिट्टी की वजह से फिसलन ज्यादा घातक हो जाती है। खासतौर पर दिसंबर-जनवरी के बीच ज्यादा ठंड और बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन आम रहती है। ऐसे में उन सड़कों से अगर भारी सैन्य वाहन गुजरते हैं, तो ऊंचाई वाली जगहों पर कई बार वाहन पर नियंत्रण मुश्किल काम होता है और उसमें चूक की आशंका बनी रहती है। हादसों पर लगाम के लिए इलाके में तैनात जवानों को खराब मौसम और परिस्थिति के मुताबिक बेहतर प्रशिक्षण तथा वाहनों के रखरखाव के पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सड़कों के बुनियादी ढांचे पर पर ठोस काम हो और उसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के इंतजाम किए जाएं, ताकि देश की सुरक्षा और आतंकवाद का सामना करने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के सामने हादसों में जान गंवाने की नौबत न आए।

क्रूरता की कड़ियां

आज वारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही दलीलों से अभी कोई नतीजा भले नहीं निकला हो, लेकिन अदालत ने इस समस्या का ठोस हल निकालने का साफ संदेश दिया है। इसके बरक्स कुछ लोगों को पशुओं के प्रति संवेदनहीनता दर्शाने और कानूनों को ताक पर रखने में हिचक नहीं हो रही है, तो यह मानवीय संवेदना और समझ पर एक सवालिया निशान है। अगर आवारा कुत्तों की वजह से कोई समस्या पैदा हो रही है, तो उससे बचाव के लिए उचित उपाय निकालने के लिए सरकार से मांग करने और अपने स्तर पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके बजाय अगर कुछ लोगों को कुत्तों को मार डालने जैसे क्रूर रास्ते अपनाना सही लग रहा है, तो यह एक बेहद अफसोसनाक स्थिति है। गौरतलब है कि तेलंगाना के याचाराम गांव में बुधवार को कुछ लोगों ने कम से कम सौ कुत्तों को कथित तौर पर जहर देकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक, ताजा घटना इस महीने तेलंगाना के कई जिलों में अब तक लगभग पांच सौ आवारा कुत्तों को मार डालने के बाद सामने आई है। यह समझना मुश्किल है कि आवारा कुत्तों के टीकाकरण, बंध्याकरण और उन्हें अनुकूल पर्यावास मुहैया कराने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग करने के बजाय लोगों को मानवीय संवेदना के न्यूनतम तकाजों को भी ताक पर रखना क्यों जरूरी लग रहा है। ऐसे लोगों को संभवतः पशु क्रूरता निवारण से जुड़े कानून की भी कोई फिक्र नहीं है, जो जानवरों को अनावश्यक दर्द पहुंचाने और पीड़ा देने से रोकता है और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है। विडंबना यह है कि आवारा कुत्तों के कार्टने या इससे जुड़ी अन्य समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकारें रिहाइशी इलाकों से उन्हें हटाने या इस समस्या का हल निकालने को लेकर ज्यादा संवेदनशील नहीं दिखतीं। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने और उनके आक्रामक होते जाने पर पहले ही उपाय कर लिए जाते, तो यह समस्या आज इतनी गंभीर नहीं होती, जितनी दिख रही है। कुत्तों के कार्टने से उपजे जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि मनुष्य अपनी बुनियादी संवेदनाओं को भी छोड़ दे।

दायित्व का बोझ और शिक्षक की गरिमा

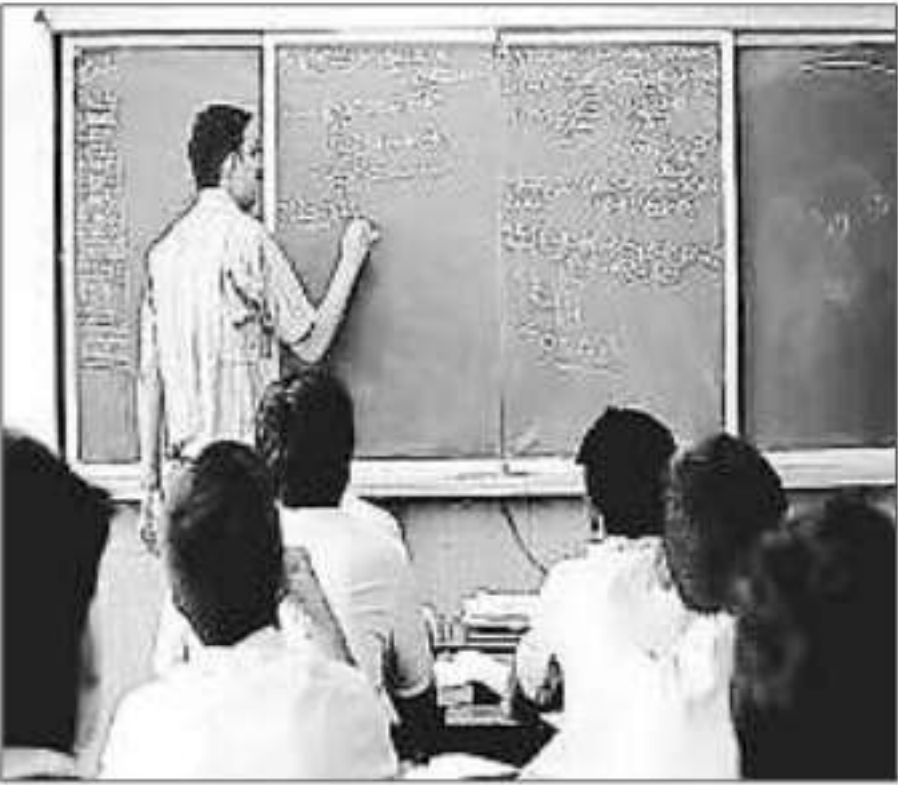
किसी भी राष्ट्र में शिक्षक की गरिमा का क्षरण उस समाज की आत्मबोधहीनता का संकेत होता है। शिक्षक की उपेक्षा किसी एक वर्ग का अपमान नहीं, बल्कि वह उस विचार की उपेक्षा होती है कि ज्ञान, विवेक और प्रश्न पूछने की क्षमता किसी समाज के लिए कितनी आवश्यक है।

मोटी सिंह

एक समय था जब शिक्षक समाज का पथप्रदर्शक माना जाता था। आज वही शिक्षक व्यवस्था की हर कमी को पूरा करने वाला सबसे सुविधाजनक संसाधन बनता जा रहा है। सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक आवश्यकताओं के नाम पर उसे ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं, जिनका असल में शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जिस बदलाव की अपेक्षा थी, कई बार उसके विपरीत भी हो रहा है। निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कुछ समय पहले शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों को आवारा कुत्तों से सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने की खबर आई। इस क्रम में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों की निगरानी तथा उनसे बचाव के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपने की भी खबर थी। औपचारिक रूप से यह व्यवस्था सुरक्षा के उद्देश्य से है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह आदेश एक गहरे और असहज प्रश्न को जन्म देता है। क्या शिक्षकों को इस तरह के या अन्य गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना शैक्षणिक दायित्वों के अनुरूप है?

शिक्षण कार्य को बेहद जिम्मेदारी का और गरिमापूर्ण कार्य माना जाता है। मगर क्या गैर-शिक्षण कार्य से संबंधित दिशा-निर्देश शिक्षकों की गरिमा के साथ न्याय करते हैं? यह प्रश्न इसलिए और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह कोई पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी, जनगणना, पशुगणना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, सत्यापन, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, कोविड निगरानी, सामाजिक अभियानों और अन्य अनेक गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगातार लगाया जाता रहा है। इन परिस्थितियों में यह बहस स्वाभाविक है कि क्या शिक्षक को अब हर प्रशासनिक दायित्व को पूरा करने वाला सुलभ मानव संसाधन मान लिया गया है? सुरक्षा और संवेदनशीलता जैसे मुद्दों की आड़ में अगर शिक्षक को उसके मूल कार्य, यानी पढ़ाने, शोध करने, अकादमिक मार्गदर्शन इत्यादि से निरंतर दूर किया जाएगा, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और समाज के बौद्धिक भविष्य पर पड़ेगा। यह सवाल अब केवल आदेश की वैधानिकता का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और प्राथमिकता का भी है।

किसी भी राष्ट्र में शिक्षक की गरिमा का क्षरण उस समाज की आत्मबोधहीनता का संकेत होता है। शिक्षक की उपेक्षा किसी एक वर्ग का अपमान नहीं, बल्कि वह उस विचार की उपेक्षा होती है कि ज्ञान, विवेक और प्रश्न पूछने की क्षमता किसी समाज के लिए कितनी आवश्यक है। अगर हम शिक्षक से निरंतर ऐसे कार्य करा रहें हैं जो उसकी पेशागत पहचान को धुंधला करते हैं, तो यह आत्मचिंतन आवश्यक है कि क्या हम अनजाने में शिक्षा को नहीं, बल्कि शिक्षक को ही अप्रासंगिक बना रहे हैं? आज जिस सहजता के साथ शिक्षकों को आवारा पशुओं की गिनती, निगरानी और नियंत्रण जैसे कार्यों में लगाने की खबरों को लिया जा रहा है, वह किसी साधारण प्रशासनिक निर्णय का परिणाम नहीं है। यह उस मानसिकता का उद्घाटन है, जिसमें शिक्षक की भूमिका को क्रमशः गौण और सुविधाजनक उपयोगितावादी बना दिया गया है। जिन कार्यों के लिए नगर निगम,



नगरपालिका परिषद और ग्राम पंचायतों में पृथक कर्मचारी, विभाग और बजट निर्धारित हैं, उन्हीं कार्यों के लिए शिक्षकों को खड़ा कर देना यह संकेत देता है कि व्यवस्था की दृष्टि में शिक्षक का समय, श्रम और बौद्धिक क्षमता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि शिक्षक अब सबसे सस्ता विकल्प बन चुके हैं।

जिस शिक्षक से समाज विवेकशील नागरिक तैयार करने की अपेक्षा करता है, उसी को आज यह अप्रत्यक्ष संदेश दिया जा रहा है कि उसका मूल दायित्व पढ़ाना, शोध करना, विचार और प्रश्न गढ़ना अब प्राथमिकता की सूची में नहीं है। कक्षा में विद्यार्थी हैं या नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता लगातार क्यों कम होती जा रही है, शोध हो रहा है या नहीं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह माना जा रहा है कि जहां प्रशासनिक तंत्र अपने किसी कार्य को करने में असफल हो जाए, वहां उसकी भरपाई के लिए शिक्षक को लगा दिया जाए। यह स्थिति केवल पेशागत गरिमा का हनन नहीं, बल्कि शिक्षा को एक कम महत्व की गतिविधि मान लेने की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करती है।

जिस शिक्षक से समाज विवेकशील नागरिक तैयार करने की अपेक्षा करता है, उसी को आज यह अप्रत्यक्ष संदेश दिया जा रहा है कि उसका

वक्त बनाम विवेक

अमित कुमार

तेजी से फैलते उपभोक्तावादी तंत्र के बीच ‘फास्ट-कामर्स’ यानी तुरंत सामान हासिल करना या उसकी आपूर्ति करने का तंत्र एक ऐसी आक्रामक व्यवस्था बनकर उभरा है, जो सुविधा के नाम पर समाज की संवेदनात्मक परतों, बाजार की स्वाभाविक लय और अर्थव्यवस्था की स्थायी संरचनाओं को भीतर ही भीतर क्षीण कर रहा है। मनुष्य की आवश्यकताओं को तात्कालिकता में बांधकर यह प्रारूप न केवल हमारी जीवन-दृष्टि को उथला बना रहा है, बल्कि पूंजी के एकाधिकारवादी विस्तार को सामाजिक अनिवार्यता के रूप में आरोपित कर रहा है। तत्काल आपूर्ति के इस कारोबार का उभार किसी साधारण तकनीकी प्रगति का संकेत भर नहीं है। यह आधुनिक पूंजीवादी संरचना की वह शाखा है, जो मानव जीवन को उत्पादन-उपभोग की निरंतर दौड़ में धकेलकर उसकी संवेदनशीलता, सामुदायिक आत्मा और संदे के आर्थिक विवेक को क्रमशः नष्ट कर रहा है। सुविधा के चकाचौंध भरे आवरण के भीतर छिपी यह व्यवस्था उपभोक्ता को उस हिंदु तक ले जाती है, जहां तात्कालिक संतुष्टि को जीवन का मूल मूल्य मान लिया जाता है और किसी वस्तु की प्राप्ति में अगर कुछ क्षणों का भी विलंब हो जाए, तो व्यक्ति उसे व्यक्तित्वत असुविधा नहीं, बल्कि जीवन में अस्वीकार्य बाधा समझ बैठता है। यही वह मनोवैज्ञानिक विकृति है, जिसे पूंजीवाद अपने महत्त्वाकांक्षी विस्तार के लिए पोषित करता है। एक ऐसा उपभोक्ता, जो संयम, प्रतीक्षा, विवेक और स्थानीय संबंधों की गरिमा को भूलकर लगातार, अनवरत, आवेगपूर्ण खरीदारी के चक्र में फंसा रहे।

यह तेज-रफ्तार प्रणाली स्थानीय बाजारों के लिए एक विषैली चुनौती बन चुकी है। पुरानी किराना संरचना, छोटे व्यापारों की आत्मनिर्भर प्रणाली और पड़ोस की जीवंत आर्थिक संस्कृति इस व्यवस्थित अतिक्रमण के आगे क्षीण होती जा रही है। तीव्रगामी वाणिज्य की विशाल कंपनियां अल्लोरिदम पर आधारित मूल्य-निर्धारण और पूंजी के असीमित संसाधनों के बल पर ऐसे दाम प्रस्तुत करती हैं, जिससे छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकते। नतीजतन, स्थानीय अर्थव्यवस्था भयावह संकुचन की ओर बढ़ती है, आटे के स्रोत केंद्रित होते जाते हैं और समाज का आर्थिक संतुलन दृष्टने लगता है। उपभोक्ता की सस्ती सुविधाओं का भ्रम मिलता है। मगर वास्तविकता यह है कि वह अपनी ही सामुदायिक आर्थिक सुरक्षा को घाटे के घाट उतार रहा होता है।

श्रम के क्षेत्र में भी यह प्रारूप अत्यंत अमानवीय परिस्थितियां निर्मित करता है। मिनटों में आपूर्ति की आकांक्षा सामान पहुंचाने वाले उन कर्मियों पर असाधारण दबाव डालती है, जिनके पास सुरक्षा, हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

मूल दायित्व पढ़ाना, शोध करना, विचार और प्रश्न गढ़ना अब प्राथमिकता की सूची में नहीं है। कक्षा में विद्यार्थी हैं या नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता लगातार क्यों कम होती जा रही है? शोध हो रहा है या नहीं, इससे अधिक महत्त्वपूर्ण यह माना जा रहा है कि जहां प्रशासनिक तंत्र अपने किसी कार्य को करने में असफल हो जाए, वहां उसकी भरपाई के लिए शिक्षक को आसानी से लगा दिया जाए। यह स्थिति केवल पेशागत गरिमा का हनन नहीं, बल्कि शिक्षा को एक कमतर महत्त्व की गतिविधि मान लेने की प्रवृत्ति को उजागर करती है। विडंबना यह है कि जिस समाज में शिक्षक को कभी गुरु, आचार्य और राष्ट्र निर्माता कहा गया, उसी समाज में उसे ऐसा बहुउद्देशीय सरकारी श्रमिक समझ लिया गया है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण और उचित पारितोषिक के कोई भी काम करवाया जा सकता है। चुनावी ड्यूटी हो, सर्वेक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण या सत्यापन हो, हर जगह शिक्षकों को आगे कर दिया जाता है।

यह धारणा धीरे-धीरे स्थापित की जा रही है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलताओं को ढोने वाला एक आज्ञाकारी माध्यम है। इस दृष्टिकोण में शिक्षक की पहचान बौद्धिक पूंजी के रूप में नहीं, बल्कि संकट-प्रबंधन के सुलभ संसाधन के रूप में होती जा रही है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इस निरंतर अपमान के बीच शिक्षक समुदाय की चुप्पी स्वयं एक सवाल बन चुकी है। यह चुप्पी केवल विवशता की नहीं, बल्कि उपेक्षा के साथ समझौता कर लेने की आदत का संकेत भी है। जब शिक्षक अपने सम्मान के सवाल पर मौन साध लेता है, तब समाज और व्यवस्था दोनों यह मान लेते हैं कि यह स्थिति न केवल स्वीकार्य है, बल्कि स्थायी भी है। यहीं से शिक्षा के क्षरण की प्रक्रिया शुरू होने लगती है।

यदि हम विकसित देशों की ओर दृष्टि डालें, तो हमें एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। फिनलैंड में शिक्षक बनना केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहां शिक्षक को गैर-शैक्षणिक सरकारी कार्यों में लगाना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि वहां पर राज्य यह समझता है कि शिक्षक का समय सीधे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा है। इसी प्रकार जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में शिक्षक न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत सम्मानित हैं। वहां शिक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह व्यवस्था की कमियों की भरपाई करे, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों की क्षमता, अनुशासन और नवाचार को आकार दे।

इन देशों की प्रगति किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि उस स्पष्ट समझ का परिणाम है जो यह मानती है कि शिक्षक को यदि कक्षा से हटाया गया, तो राष्ट्र दिशा से भटक जाएगा। वहां शिक्षकों से पशुओं की गुणना और निगरानी नहीं करवाई जाती, बल्कि संभावनाओं की गिनती करवाई जाती है। वहीं यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षक का अपमान दीर्घकाल में राष्ट्र के लिए एक खतरे का संकेत है। अंततः यह सवाल किसी एक आदेश, किसी फाइल या किसी विभाग तक सीमित नहीं है, यह उस बौद्धिक आत्मा का प्रश्न है जिसे हम राष्ट्र के रूप में गढ़ रहे हैं। जब शिक्षक से उसका मूल धर्म छीन कर उसे व्यवस्था की असफलताओं का मूक वाहक बना दिया जाता है, तब शिक्षा उपेक्षित ही नहीं होती, बल्कि अज्ञान को संस्थागत वैधता मिल जाती है। क्या कोई समाज सचमुच प्रगति की आकांक्षा कर सकता है, जहां शिक्षक नहीं, बल्कि सड़कों पर अन्य कार्य करता हुआ अधिक उपयोगी समझा जाए?

संकल्प से सिद्धि

अब भारत केवल स्वप्न नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का अमध्य साहस रखता है। हमारी विकास यात्रा संकल्प से सिद्धि के उस मंत्र पर टिकी है, जहां हर बाधा एक नए अवसर में बदल जाती है। पिछले कुछ वर्षों, विशेषकर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। यह केवल एक तकनीकी मिशन नहीं था, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की सामूहिक जीत थी। इसी कड़ी में गगनयान की गूंज और आदित्य-एल1 के जरिए सूर्य के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में बढ़ाए गए कदमों ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। विकास के यह लहर केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं हैं। वर्ष 2026 की दहलीज पर खड़ा देश अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत चिप का स्वदेशी निर्माण हमारी तकनीकी संप्रभुता का जीवंत प्रतीक बन चुका है।

- समीक्षा मिश्रा, जम्मू

सफलता का पैमाना

आज के दौर में सफलता का पैमाना बदल गया है। मानवीय मूल्यों की जगह अब भौतिक संपदा ने ले ली है। धन केवल एक साधन है, लेकिन विडंबना यह है कि इस समय समाज में यह साधन न रह कर स्वयं में एक ‘साध्य’ बन गया है। जब साधन ही लक्ष्य बन जाए, तो सामाजिक और नैतिक पतन तय है। धन के प्रति बढ़ता मोह एक मानसिक रोग की तरह फैल रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रगति की तुलना दूसरे की संपत्ति से करने लगता है,

लत का हासिल

शल मीडिया दोधारी तलवार की तरह है, जो आभासी ही सही, लेकिन लोगों को जोड़ती है। मगर साथ ही लत, चिंता, अवसाद और नींद में खलल जैसी परेशानियां भी पैदा करती है। अत्यधिक उपयोग से मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया के खिलाफ 19 वर्षीय एक अमेरिकी युवती अदालत तक चली गई। आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया मंच को इस तरह से बनाया गया है कि यह युवा उपयोगकर्ताओं की मानसिक सेहत के

समाज इतनी तेजी से बदल रहा है कि संबंध एक शब्द बन कर रह गया है। या कहें कि कहने के लिए हम किसी से संबंध बना तो लेते हैं, लेकिन उसे निभाने में सफल नहीं हो पाते। इन दिनों संबंधों में दूरी या अलगाव आम बात होती जा रही है। वह मां-बाप और बच्चों के बीच हो या फिर पति-पत्नी के बीच, कई बार हम इन्हें सोच के फर्क की बात कह कर न्यायसंगत मान लेते हैं, लेकिन पति-पत्नी के बीच विच्छेद में थोड़ी अलग बात भी है। आज के समय में जहां रिश्ते बनाने से पहले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के बाद शादी की निर्णय लेते हैं, तो फिर कुछ समय बाद ही सोच में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है जिससे संबंधों में दरार आ जाती है। सच है कि दो लोगों की सोच हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन हर बार इसका समाधान अलगाव तो नहीं हो सकता।

- अभिषेक जैसवाल, मैहर, मप्र



विकासपुरी, जनकपुरी हिंसा मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 22 जनवरी।

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने से संबंधित मामले में गुरुवार को बरी कर दिया। अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। कुमार साल 2018 से जेल में बंद हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक-दो नवंबर 1984 को पालम कालोनी में पांच लोगों की हत्या से जुड़े मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत पीड़ितों और उनके परिवारों की ओर से झेली गई पीड़ा को समझती है, लेकिन उसका निर्णय ‘भावनाओं से परे’ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराने का फैसला पेश

‘विश्व की समस्याओं का समाधान भारतीय परंपराओं में निहित है’

जनसत्ता संवाददाता हरिद्वार, 22 जनवरी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि विश्व की समस्याओं का समाधान भारतीय परंपराओं में निहित है। शाह ने हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारत और उसकी संस्कृति को समझता है, वह जानता है कि विश्व की समस्याओं का समाधान भारतीय परंपराओं में निहित है।

उत्तराखंड की पावन भूमि विशेषकर सप्तर्षि भूमि हरिद्वार में आकर हजारों वर्षों की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है।

शांतिकुंज के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के योगदान का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि भारत उनके उपकारों से कभी ऋमुक्त नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र को जन-जन तक सर्वसुलभ बनाया, वैश्विक मानवतावाद की अवधारणा को सुदृढ़ किया और वैज्ञानिक अस्थित्वावाद को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। पंडित श्रीराम शर्मा का सरल सूत्र ‘हम बदलेंगे, युग बदलेगा’ राष्ट्र परिवर्तन की कुंजी है और गायत्री महामंत्र केवल संस्कृत का मंत्र नहीं, बल्कि जप करने वाले साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला जीवन मंत्र है। उन्होंने सनातन धर्म में व्याप्त विकृतियों को दूर कर आध्यात्मिकता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा तथा समानता, संस्कृति, एकता और अखंडता के मूल्यों को सुदृढ़ किया। पंडित श्रीराम शर्मा ने ‘व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण’ के विचार को व्यवहार में उतारने का मार्ग प्रशस्त किया।

पेज 1 का बाकी

गाजा शांति निकाय से भारत का किनारा

राष्ट्र के साथ मिलकर न केवल पश्चिम एशिया में, बल्कि अन्य जगहों पर भी युद्धों को सुलझाने में मदद कर सकता है।’ हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के साथ किस प्रकार सहयोग करेगा।पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के निमंत्रण के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

उन्होंने बताया कि भारत इस पहल के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है क्योंकि इसमें कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। भारत फिलस्तीन मुद्दे के लिए ‘दो-राष्ट्र समाधान’ पर जोर दे रहा है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ अगल-बगल रहें। ‘शांति बोर्ड’ में शामिल करने के लिए दिए गए आमंत्रण को अंतर्द्वीीन, अल्बानिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाखिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ने स्वीकार किया है।फ्रांस, नावै, स्लोवेनिया, स्वीडन और ब्रिटेन उन देशों में शामिल हैं जो अभी बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप द्वारा आमंत्रित, लेकिन अब तक कोई प्रतिबद्धता नहीं जताने वाले देशों में कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, यूनान, इटली, पैरग्वे, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और यूक्रेन शामिल हैं। ट्रंप ने कहा, ‘यह केवल अमेरिका के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है। मुझे लगता है कि गाजा में सफलता मिलने के बाद हम इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकते हैं।’ समारोह में उपस्थित नेताओं में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल थे। ट्रंप के ‘शांति बोर्ड’ को अमेरिका द्वारा गाजा और उसके बाहर शांति और स्थिरता लाने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में पेश किया जा रहा है। इस पहल से अटकलें लगाई जा रही हैं कि ‘शांति बोर्ड’ संयुक्त राष्ट्र के

किए गए सबूतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, अभियोजन पक्ष ने जिन गवाहों से जिरह की, उनमें से ज्यादातर के बयान सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं और/या वे ऐसे गवाह हैं, जिन्होंने तीन दशकों तक आरोपी का नाम नहीं लिया। ऐसे गवाहों द्वारा आरोपी की पहचान किए जाने पर भरोसा करना ‘जोखिम भरा होगा और इससे अन्याय हो सकता है।’

उन्होंने कहा कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कुमार अपराध स्थल पर मौजूद थे या

उन्हें वहां किसी ने देखा था। इस घटना के सिलसिले में दंगाई भीड़ को उकसाने या साजिश रचने का भी कोई सबूत नहीं है।

इस बीच, शिकायतकर्ता हरविंदर सिंह के वकील मनिंदर सिंह ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के संकेत दिए। मनिंदर ने कहा कि हम पहले फैसले का गहन अध्ययन करेंगे और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।



बंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा से बाहर निकलते समय राज्याल थावरचंद गहलोट को रोकने की कोशिश की गई।

राज्यपाल ने तीन वाक्य में समाप्त किया संबोधन कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उन्हें केंद्र सरकार की ‘कठपुतली’ करार दिया

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जनवरी।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोट ने गुरुवार को राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अपना परंपरागत अभिभाषण केवल तीन वाक्यों (सरकार द्वारा तैयार किए गए विस्तृत भाषण के पहले और आखिरी वाक्यों समेत) में समाप्त कर दिया जिसे लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल पर अपना खूद का विचार व्यक्त करने का आरोप लगाया और उन्हें केंद्र सरकार की ‘कठपुतली’ करार दिया। गैर-भाजपा शासित तीन दक्षिणी राज्यों (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक) में दो दिनों में राज्यपाल और सरकार के बीच तीसरी बार टकराव हुआ है। विधानसभा व विधानपरिषद

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद स्थल पर वसंत पंचमी के दिन शुक्रवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने, जबकि मुसलमानों को अपराह्न एक बजे से तीन बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने गुरुवार को यह भी निर्देश दिया कि नमाज के लिए आने वाले मुसलिम समुदाय के लोगों की सूची जिला प्रशासन को दी जाए।

हिंदू और मुसलिम समूहों ने 23 जनवरी शुक्रवार को भोजशाला परिसर में धार्मिक रस्मों के लिए अनुमति मांगी थी। उस दिन वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा भी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों से परस्पर सम्मान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। पीठ ने कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता और



महाधिवक्ता, दोनों ने उचित सुझाव दिया है कि यह जानने के बाद कि कल (शुक्रवार) दोपहर एक से तीन बजे के बीच नमाज के लिए मुसलिम समुदाय से कितने लोगों के आने की संभावना है, परिसर के भीतर एक विशेष और अलग स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि निर्धारित समय पर नमाज अदा की जा सके।

न्यायालय ने कहा कि इसी प्रकार, पहले की तरह, वसंत पंचमी के अवसर पर पारंपरिक अनुष्ठान के लिए हिंदू समुदाय को एक अलग स्थान उपलब्ध कराया जाए। पीठ ने जिला प्रशासन को उस स्थान पर कानून व्यवस्था बनाए

निर्वाचन आयोग का नया एप ‘ईसीआइनेट’ जारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भ्रामक सूचनाओं से मुकाबले का हथियार बताया

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जनवरी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को मतदाताओं, अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक नया डिजिटल ऐप जारी किया। उन्होंने ‘ईसीआइनेट’ को गलत सूचनाओं के प्रसार की चुनौती से निपटने के लिए एक औजार करार दिया क्योंकि इस पर चुनाव संबंधी सभी तथ्य उपलब्ध हैं।

‘ईसीआइनेट’ अपने 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को एकीकृत करेगा।

लिपि एक एकल मंच प्रदान करेगा। यह नया मंच उपयोगकर्ताओं पर कई एप डाउनलोड करने, ‘नेविगेट करने’ और विभिन्न आइडी याद रखने के बोझ को कम करेगा। इसके अतिरिक्त, ईसीआइनेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर प्रारसंगिक चुनावी डेटा तक पहुंचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआइनेट पर डेटा केवल निर्वाचन आयोग के

अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।

संबंधित अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी टकराव की स्थिति में

जनगणना के पहले चरण में पूछे जाएंगे 33 सवाल, अधिसूचना जारी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जनवरी।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को 33 प्रश्नों की सूची जारी की, जो एक अप्रैल से शुरू होने वाले जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाएंगे। राजपत्र अधिसूचना में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने घर के फर्श और छत में प्रयुक्त सामग्री, वहां रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या, घर का मुखिया पुरुष है या महिला, उपभोग किए जाने वाले अनाज का प्रकार, बुनियादी एवं आधुनिक आवश्यकताओं तक पहुंच और स्वामित्व वाले वाहनों के प्रकार जैसे प्रश्न सूचीबद्ध किए हैं।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार निर्देश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में आवास

स्मारक है। एएसआइ द्वारा सात अप्रैल 2003 को की गई एक व्यवस्था के तहत, हिंदू समुदाय के सदस्य मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना करते हैं, जबकि मुसलिम समुदाय के सदस्य शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करते हैं।

न्यायालय ‘हिंदू फ्रंट फार जस्टिस’ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा। याचिका में, वसंत पंचमी पर हिंदुओं की पूजा-अर्चना करने का विशेष अधिकार देने का अनुरोध किया गया था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मार्फत दायर याचिका पर मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था। जैन ने कहा था कि एएसआइ के 2003 के आदेश में शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी पड़ने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने वसंत पंचमी पर पूरे दिन हिंदुओं के लिए विशेष, निर्बाध पूजा-अर्चना की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सुनवाई के दौरान, जैन ने दलील दी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और हवन होंगे और उन्होंने पूरे दिन पूजा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

वैधानिक प्रपत्रों में विधिवत भरा हुआ प्राथमिक डेटा मान्य होगा। ईसीआइनेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट एप, ‘सीविजल’, सुविधा, सक्षम और केवाईसी एप जैसे मौजूदा एप को समाहित कर देगा, जिसके कुल मिलकर 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को उनकी भाषाओं में और उनके कानूनों के अनुसार इसी तरह का उपकरण विकसित करने में सहायता की पेशकश की। कुमार ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों ने भ्रामक सूचना के विषय पर चिंता व्यक्त की थी।

दस जवानों की मौत, 11 घायल

बताया कि सेना का एक वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 10 जवानों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, डोडा में खराब मौसम के बीच दुर्गम इलाके से गुजर रहा सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा। इस वाहन में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए जा रहे सैनिक सवार थे। हादसे में कई जवान हताहत हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। हमने अपने बहादुर सैन्यकर्मियों को खो दिया। देश उनकी सेवाओं के लिए उन्हें हमेशा याद रखेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हादसे पर गहरा दुःख

जताया। राजनाथ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, मैं डोडा में हुए सड़क हादसे से बेहद दुखी हूं, जिसमें हमने भारतीय सेना के 10 बहादुर जवानों को खो दिया। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डोडा की घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताया। एक्स पर पोस्ट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुःख की घड़ी में हम सब वीर जवानों के शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हैं। सेना के उत्तरी कमांडर ने कहा कि जनरल आफिसर कर्मांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और कमान के सभी रैंक के जवान वीरों को सलाम करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के असामयिक निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तरी कमान के सभी सदस्य शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और हादसे में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

तमिलनाडु में राजग की बैठक, प्रधानमंत्री आज करेंगे चुनावी शंखनाद

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जनवरी।

तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अन्नाद्रमुक नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की चली लंबी बैठकों के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। राज्य की 234 विधानसभाओं के लिए शुरु हो रहे प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री उपनगरीय क्षेत्र मद्रुरांतकम से करेंगे।

साल 2021 में हुए सोलहवीं विधानसभा चुनाव में राजग को हार का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी पीयूष गोयल ने सहयोगी दलों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। गोयल ने आगामी विधानसभा

प्रधानमंत्री की रैली से पहले अन्नाद्रमुक नीत राजग की बैठक, परखा गया गठबंधन का गणित, गठबंधन में हुई दिनावरन की वापसी

चुनावों में इस गठजोड़ के शानदार जीत हासिल करने का दावा करते हुए द्रविड़ मुनेत्र कषमग (द्रमुक) के ‘भ्रष्ट और वंशवादी शासन’ का अंत होने की बात कही।

बाद में, दोनों नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पलानीस्वामी ने कहा कि 23 जनवरी को चेन्नई के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले एक निर्णायक मोड़ साबित होगी, क्योंकि यह ‘भ्रष्ट द्रमुक सरकार’ की पराजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। गोयल की अन्नाद्रमुक महासचिव के ग्रीनवेज

रोड स्थित आवास में नाश्ते पर हुई बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री की चुनावी रैली से पहले राज्य में राजग को अंतिम आकार देना था। तमिलनाडु में राजग का नेतृत्व अन्नाद्रमुक कर रही है, और राज्य में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में भाजपा, पीएमके (अंबुमणि गुट), एएमएमके और पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासुन के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कांग्रेस शामिल हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल ने मांग की कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और उउ मुख्यमंत्री उदयनिधि को पद से हटाए। सनातन धर्म पर कथित नफरती भाषण के लिए उदयनिधि के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश परित करने के सिलसिले में उन्होंने यह मांग की। गोयल ने कहा कि हम उदयनिधि स्टालिन की राष्ट्रीयरोधी टिप्पणियों का सख्त विरोध करते

हैं। मैं मांग करता हूं कि उन्हें सरकार से हटाया जाए और उनके नफरती भाषण, लोगों को बांटने और सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पलानीस्वामी से मुलाक़ा के दौरान गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नव निर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से शुभकामनाएं दीं। गोयल ने ‘एक्स’ पर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी और तमिलनाडु में थिरु पलानीस्वामी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजग ‘भ्रष्ट, अक्षम, समझौतावादी और विकास विरोधी द्रमुक सरकार’ को पूरी तरह से सत्ता से बाहर कर देगा। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी ढांचा, विकास और सुशासन लाएंगे। हम महिलाओं, बच्चों, युवाओं, मधुआरों, किसानों और समाज के हर वर्ग के लिए काम करेंगे।

ख़बर कोना



मुंबई में शिवाजी पार्क परेड मैदान में गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वभ्यास में भाग लेते पुलिसकर्मी।

पश्चिमी समर्पित माल गलियारा से जुड़ेगा न्यू रेवाड़ी-कुंभावास खंड

नई दिल्ली, 22 जनवरी (ब्यूरो)।

दिल्ली-एनसीआर से नवी मुंबई तक सीधे तीव्र माल ढुलाई के लिए तैयार हो रहे पश्चिमी समर्पित माल गलियारा से न्यू रेवाड़ी-कुंभावास खंड जुड़ सकता है। समर्पित माल ढुलाई गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) इस दिशा में संभावनाएं तलाश रहा है। साथ ही माल को उतारे व चढ़ाने के लिए अन्य विकल्प की तलाश की जा रही है। दरअसल, डीएफसीसीआइएल के अधिकारियों ने उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ न्यू दादरी-रेवाड़ी-अटली खंड का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान तैयार हो रहे गलियारे पर मालगाड़ियों के परिचालन, तकनीकी व्यवस्थाओं और भविष्य में संपर्क की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएफसीसीआइएल के निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) शोभित भटनागर, उत्तर रेलवे की प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक डाक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने न्यू दादरी से अटली तक रेल अवसंरचना, वायाडक्ट और सुरंगों की सुरक्षा व कार्यक्षमता का अकालन किया गया। अधिकारियों ने न्यू दादरी स्टेशन पर सुविधाओं की समीक्षा, निरीक्षण किया।

पेटेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी होगी धान की दो नई किस्में

नई दिल्ली, 22 जनवरी (ब्यूरो)।

कम उर्वरक, कम कीटनाशक और सूखे(कम पानी) में भी जीनोम संपादन जरिए फसलों की बेहतर पैदावार के लिए वैज्ञानिकों ने धान की दो किस्में विकसित की हैं। अलग-अलग प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का इस्तेमाल कर विकसित की गई दोनों किस्में, पेटेंट संबंधी प्रक्रिया के पूरा होने पर वाणिज्यिक रूप से जारी की जाएंगी। वैज्ञानिकों ने फसल सुधार के जरिए चावल की दोनों किस्में(कमला और डीएसटी, राइस-1) विकसित की हैं। कमला की बालियों में बालियों में दाने अधिक हैं, जिससे पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। बीपीटी 5204 में सुधार के बाद नई किस्म कमला विकसित की गई। चावल की दूसरी किस्म, डीएसटी-1 जो एटीयू 1010 का सुधार है। इस किस्म में सूखा और लवणता बर्दाश्त करने की क्षमता होने की वजह से बेहतर पैदावार की उपासि संभावना है। इससे उन क्षेत्रों चावल की बेहतर पैदावार हो सकेगी, जहां कम पानी या सूखे की वजह से अब तक चिंता बनी हुई थी।

बलौदाबाजार-भाटापारा के इस्पात संयंत्र में विस्फोट, छह मजदूरों की मौत

नई दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में गुरुवार सुबह एक इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में छह मजदूरों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। जिलाधिकारी दीपक सोनी ने बताया कि यह घटना बकुलाही गांव में स्थित 'रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड' में सुबह नौ बजकर 40 मिनट पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद संयंत्र से दूर-दूर तक धुएं का गुबार उड़ता देखा गया। मजदूरों के शव जली हुई हालत में थे। ज्यादातर मजदूर बिहार व झारखंड के निवासी थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भट्टी से जुड़े 'इस्ट सेटिंगिंग चेंबर' (डीएससी) में 'विस्फोट के बाद से रिसाव होने लगा।' 'डीएससी' वह जगह होती है जिसमें उच्च तापमान वाली राख पहुंचाई जाती है। रिसाव के कारण गरम राख कर्मचारियों पर गिर गई जिससे छह कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई।

दावोस में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संधवी ने कहा भारत एक दशक में महत्त्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक शक्ति बना

दावोस, 22 जनवरी (भाषा)।

भारत ने पिछले दशक में एक 'उभरती' अर्थव्यवस्था की अपनी से छवि से बाहर निकल कर खुद को 'महत्त्वपूर्ण' वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में तब्दील किया है जिसकी नींव मजबूत वृद्धि एवं व्यापक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संधवी ने यहां आयोजित एक सत्र में यह बात कही।

सीआइआइ और केपीएमजी द्वारा आयोजित सत्र में नायडू ने बुधवार को कहा कि भारत आज विश्वास, पैमाने एवं नवाचार के संगम पर खड़ा है। भारत अपने स्थिर लोकतांत्रिक संस्थानों के जरिए भरोसेमंद व्यवस्था, अपनी विविधता एवं आकार के जरिए मजबूती और क़ियायती एवं मूल्यवर्धित समाधान देकर प्रारसंगिकता प्रदान करता है। संधवी ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों तक भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता रहा लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है।

उन्होंने कहा, 'भारत अब केवल उभरता हुआ देश नहीं रहा बल्कि वह वैश्विक वृद्धि के लिए, मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं के लिए, लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए तथा नवाचार, निरंतरता एवं समावेशी विकास के भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभा रहा है।' इसी भावना को दोहराते हुए नायडू ने कहा, 'भारत को अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। भारत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य बनता जा रहा है।' नायडू ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के इतर आयोजित सत्र में कहा कि भारत की वर्तमान वृद्धि व्यापक है, डिजिटल रूप से सक्षम है, मजबूत अवसंरचना से समर्थित एवं समावेशी है। उन्होंने कहा, 'यह वही वास्तविक बदलाव है जो भारत ने पिछले एक दशक में देखा है। भारत के विकास माडल में सबसे महत्त्वपूर्ण बदलावों में से एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण रहा है।

चुनाव आयोग ने तृणमूल विधायक पर मुकदमा दर्ज करने को कहा

कोलकाता, 22 जनवरी (भाषा)।

चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के फरक्का प्रखंड विकास कार्यालय (बीडीओ) में हुई तोड़फोड़ के संबंध में राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोनिरुल इस्लाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश गुरुवार को दिया। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आयोग ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि गुरुवार शाम पांच बजे तक प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक मोनिरुल इस्लाम ने अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर फरक्का बीडीओ कार्यालय के बाहर मतदाता सूची के विशेष गहन

राजस्व लक्ष्य से ढाई फीसद पीछे रही रेलवे की ढुलाई

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 22 जनवरी।

भारतीय रेलवे का अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच माल परिवहन लक्ष्य से करीब ढाई फीसद पीछे रहा। हालांकि साल 2024 के मुकाबले करीब तीन फीसद से अधिक की बढ़त दर्ज हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवंबर 2025 माह की बुनियादी ढांचा क्षेत्र की समीक्षा रपट के मुताबिक रेलवे ने अप्रैल-नवंबर 2025 के लिए रेलवे ने 1098.640 मिलियन टन रेलवे राजस्व माल यातायात का लक्ष्य रखा था। लेकिन रेलवे 1070.790 मिलियन टन ही रेलवे राजस्व माल यातायात कर सकी। इसमें 50 फीसद हिस्सेदारी कोयले की रही। जबकि लोह



दावोस में विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संधवी ।

स्मृति ईरानी की अगुआई वाले गठबंधन ने 20 लाख डालर जुटाए

भारत में महिला उद्यमियों के लिए 10 करोड़ डालर का कोष बनाने की योजना पर काम कर रही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक में महज दो दिनों के भीतर 20 लाख डालर की प्रतिबद्धता जुटा ली है। यह कोष देशभर की महिला-स्वामित्व वाली एक लाख लघु इकाइयों को सहयोग देने के लिए प्रस्तावित है। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी इस बैठक के दौरान ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें 2024 में दावोस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का अवसर मिला था।

यूरोपीय संघ ने निर्यात लाभ छूट को रोका, भारत से कारोबार पर असर संभावित

नई दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा)।

यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक जनवरी, 2026 से भारत और दो अन्य देशों को सामान्यीकृत तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) के तहत कुछ क्षेत्रों को दिए गए विशेष निर्यात लाभ को स्थगित कर दिया है।

यह कदम 27 देशों वाले इस समूह को

महाशक्तियों के लिए यह साथ आने का अवसर : मर्ज

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित एफटीए पर हस्ताक्षर से चंद दिनों पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गुरुवार को कहा कि 'महाशक्तियों का युग' नियम-आधारित मुक्त व्यापार का समर्थन करने वाले देशों के लिए एक अवसर है।

भारत से होने वाले निर्यात पर असर डालेगा।

यह घटना इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है कि भारत और यूरोपीय संघ 27 जनवरी को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर बातचीत पूरी होने की घोषणा कर सकते हैं।

यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल के मुताबिक, यूरोपीय आयोग ने सितंबर, 2025 में नियम जारी किए थे, जिनके तहत जीएसपी



भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले गुरुवार को राष्ट्रीय झंडे की खरीदारी करती महिलाएं।

भू-राजनीतिक तनाव घटने से बाजार में लौटी तेजी रुपया सात पैसे सुधरकर 91.58 प्रति डालर पर बंद

मुंबई, 22 जनवरी (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के संभावित हस्तक्षेप से रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले गुरुवार को रिकार्ड निचले स्तर से मामूली सुधार के साथ सात पैसे बढ़कर 91.58 प्रति डालर पर बंद हुआ। देशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सकारात्मक टिप्पणियों से भी बाजार धारणा में सुधार हुआ। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर भविष्य के एक समझौते का ढांचा तय हो गया है और एक फरवरी से यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित शुल्क को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा।

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 91.54 पर खुला। कारोबार के दौरान रुपए ने

नई दिल्ली

दावोस, 22 जनवरी (भाषा)।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारत ने आर्थिक परिदृश्य के सभी क्षेत्रों में साझेदारी के लिए अपनी स्पष्ट इच्छा जाहिर की है और वैश्विक कर्ज से जुड़ी चिंताओं के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। वैष्णव ने यहां कहा कि इस बार का संदेश है कि भारत के साथ साझेदारी करें और भविष्य से जुड़ें।'

यहां मौजूद सभी 10 राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद के मंत्र के अनुरूप अपनी संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, 'यहां भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्ष में भारतीय



अर्थव्यवस्था को किस तरह बदला और (क्षेत्रों के लिए) खोला है।मंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को यह भी बताया है कि वह नए विचारों के लिए भी खुला है। उन्होंने कहा, 'चाहे सेमीकंडक्टर उद्योग हो, कृत्रिम मेधा (एआइ) हो, विनिर्माण हो, हरित ऊर्जा हो या कोई अन्य क्षेत्र...हम हर जगह दुनिया के साथ साझेदारी करना चाहते हैं।'

यहां 10 राज्यों की भागीदारी पर उन्होंने कहा, 'सभी राज्य मेहनत कर रहे हैं और जब राज्य विकास करते हैं तो देश अपने आप विकसित होता है। प्रधानमंत्री मोदी का राज्य स्तर का अनुभव अब पूरे देश को लाभ पहुंचा रहा है।' अमीर देशों में बढ़ते कर्ज को लेकर भारत की चिंता को लेकर किए सवाल पर वैष्णव ने कहा कि अपनी व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनका कर्ज स्तर कम है।

यह छूट अब लगभग सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों- खनिज, रसायन, प्लास्टिक, रबर, वस्त्र और परिधान, पत्थर एवं सिरमिक, कीमती धातुएं, लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं और परिवहन उपकरण से हटा दी गई है। ये क्षेत्र भारत के यूरोपीय निर्यात का प्रमुख आधार हैं। 87 फीसद निर्यात अब उच्च आयात शुल्क के अधीन होंगे।

डाक विभाग का लक्ष्य राजस्व में 30 फीसद की वृद्धि करना : सिंधिया

नई दिल्ली, 22 जनवरी (ब्यूरो)।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि डाक विभाग ने चालू वित्त वर्ष में राजस्व में 30 फीसद की वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा है। डाक विभाग (डीओपी) की 2025-26 तीसरी (अक्तूबर-दिसंबर) तिमाही समीक्षा के बाद मंत्री ने कहा कि छह में से पांच क्षेत्रों के राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई जबकि अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय डाक का राजस्व स्थिर रहा। सिंधिया ने कहा, '2025-26 के लिए हमारा लक्ष्य 17,546 करोड़ रुपए है जिसका मतलब है कि हम वित्त वर्ष 2024-25 के 13,240 करोड़ रुपए से एक ही वित्त वर्ष में राजस्व का 30 फीसद की वृद्धि का लक्ष्य रख रहे हैं।'



91.48 के उच्च स्तर और 91.68 के निचले स्तर को भी छुआ। लेकिन अंत में यह 91.58 प्रति डालर पर बंद हुआ जो इसके अब तक के सबसे निचले स्तर से सात पैसे अधिक है। बुधवार को रुपया 68 पैसे टूटकर डालर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर 91.65 पर बंद हुआ था।

सेंसेक्स 398 अंक चढ़ा, निफ्टी में 132 अंकों की बढ़त वैश्विक बाजारों में मजबूती और ग्रीनलैंड मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम रुख अपनाने से गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीन सत्रों की गिरावट से उबरने में सफल रहे। सेंसेक्स 398 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 132 अंकों की तेजी रही। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपए में हल्का सुधार आने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी निवेशक धारणा को समर्थन मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स उतार-चढ़ाव के बीच 97.74 अंक बढ़कर 82,307.37 अंक पर बंद हुआ।

सुप्रीम कोर्ट से चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह

पुनरीक्षण

बिना किसी टोस आधार के जांच नहीं की जा सकती

निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित बताया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जनवरी।

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) करने संबंधी निर्णय को 'निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित' बताया और सुप्रीम कोर्ट से बिहार में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया। आयोग ने दलील दी कि कुछ गैर सरकारी संगठनों और नेताओं के इशारे पर विशेष पड़ताल के नाम पर बिना किसी टोस आधार के जांच नहीं की जा सकती।

एडीआर (एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स), पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टी) तथा कुछ सांसदों के कहने पर बिना किसी टोस आधार के जांच की

निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि बिहार एसआइआर से जिन 66 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, उनमें से कोई भी इस अदालत या हाई कोर्ट में नहीं आया और न ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई याचिका दायर की।

अनुमति नहीं दी जा सकती। वरिष्ठ वकील ने बिहार समेत विभिन्न राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा एसआइआर करने के निर्णय को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के दौरान ये दलीलें पेश कीं। उन्होंने उस फैसले का जिक्र किया जिसमें शीर्ष अदालत ने मतपत्रों को फिर से लागू करने और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को रद्द करने की याचिका



खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि संक्षेप में, हमें यूरोप का अनुसरण करना चाहिए। अगर वे ईवीएम को अपनाते हैं, तो हमें भी इसे अपनाना चाहिए। और अगर वे मतपत्रों को अपनाते हैं, तो हमें भी इसे अपनाना चाहिए। एक व्यक्ति अखबार में लेख लिखता है और दूसरा व्यक्ति उसी का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करता है।

द्विवेदी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ से अपील की कि वे एसआइआर का बचाव करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दें और साथ ही ज़ुर्माना भी लगाया जाये, क्योंकि एसआइआर की कवायद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, वैधानिक शक्तियों का एक वैध और पारदर्शी प्रयोग है।

द्विवेदी ने दलील दी कि एक बार जब निर्वाचन आयोग 1950 के अधिनियम की धारा 21(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तो विशेष पुनरीक्षण करने का तरीका और प्रक्रिया पूरी तरह से उसके विवेक पर निर्भर करती है। बिहार में लगभग 20 साल से एसआइआर कवायद नहीं की गई थी और इसे शहरीकरण और जनसंख्या के आवागमन समेत

बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए किया गया। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग का यह तर्क मान लिया जाता है कि धारा 21(3) बिना किसी रोक-टोक के विवेक का अधिकार देती है, तो 'मामला वहीं खत्म हो जाएगा।' न्यायमूर्ति बागची ने सवाल किया कि क्या बदला हुआ नागरिकता ढांचा मौजूदा एसआईआर का कारण था, और कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेश में साफ तौर पर सीमा पार या अवैध प्रवासन को इसका आधार नहीं बताया गया था।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि आमतौर पर 'प्रवासन' शब्द का मतलब कानूनी आवाजाही होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना संवैधानिक अधिकार है। द्विवेदी ने कहा कि यह संशोधन पहले कभी लागू नहीं किया गया था।

दुनिया की चिंता करता है भारत, कई देशों की संकट में की मदद : भागवत

जागरण संवाददाता, जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचचालक मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया के देश आजकल अपने स्वार्थ के साथ चल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए लेकिन भागत के लोग कभी इस सोच के साथ नहीं चले और न ही चलेंगे क्योंकि भारतीय धर्म को जानते हैं। भारत केवल अपने हित की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता करता है। भारत ने बिना किसी स्वार्थ के पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों की संकट में मदद की है। भागवत ने गुरुवार को राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के छोटी खादू कस्बे में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के मर्यादा महोत्सव को संबोधित करते हुए यह बात कही।

सर संचचालक ने कहा कि हमारे



मोहन भागवत ● फाइल फोटो

पूर्वज धर्म का सत्य जानते थे। धर्म के पीछे जो सत्य है वो बाकी दुनिया नहीं जानती थी, इसलिए सत्य, अहिंसा व अपरिग्रह आदि बातें केवल हमारे देश में हैं।

उन्होंने मर्यादा, अनुशासन और संतुलन को राष्ट्र प्रगति की नींव बताते हुए कहा कि धर्मग्रंथों का संदेश जीवन की दिशा बदल सकता है। इस मौके पर जैन श्वेतांबर तेरापंथ संमदाय के सर्वोच्च आचार्य महाश्रमण ने खोज, अहिंसा और करुणा का महत्व बताया।

एक नजर में

छत्तीसगढ़ के स्टील प्लांट में

ब्लास्ट, छह श्रमिकों की मौत

भाटापारा: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार -भाटापारा जिले में रियल स्टील संयंत्र में गुरुवार सुबह एक भीषण हादसे ने छह श्रमिकों की मौत हो गई। प्लांट में डस्ट सेटलिंग वैबर के फटने से निकली अत्यधिक गर्म राख और डस्ट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि डस्ट सेटलिंग वैबर का तापमान अत्यधिक होता है, जिससे राख लीक होकर नीचे काम कर रहे श्रमिकों पर गिर गई। हादसे में बिहार के गया के रहने वाले वषण कुमार, राजदेव कुमार, जितेंद्र भुइया, बदरी भुइया, विनय और सुन्दर भुइया की मौत हो गई। (नईदुनिया न्यूज़)

बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली : संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू आगामी बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को संसद के दोनों सदनों के पेलोर लीडर्स की सर्वदलीय बैठक आयोजित करेंगे। बैठक में सत्र का एजेंडा तय होने और सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक संसद के मुख्य समिति कक्ष में होगी। उम्मीद है कि सरकार इस बैठक में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और आगामी सत्र के दौरान दोनों सदनों के समक्ष आने वाले विधायी कामकाज पर चर्चा करेगी। (एएनआई)

बंगाल में पेट्रोल डालकर भाजपा नेता का घर फूँका, तोड़फोड़ की

कोलकाता : बंगाल में बांकुड़ा जिले के आँदा में भाजपा नेता तापस बारिक के घर में कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, तोड़फोड़ की। उन्होंने आरोप लगाया कि तुणमूल कांग्रेस समर्थित बदमाशों ने ऐसा किया है। उनका उद्देश्य उनकी तथा परिवार के सदस्यों की हत्या करना था। ग्रामीणों के प्रयासों से सभी बच गए। भाजपा ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। (राष्ट्र)

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में देहरी पूजन को लेकर सेवायत व समिति में विवाद

वृंदावन : ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में देहरी पूजन की परंपरा पर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने रोक लगा रखी है। देहरी तक पहुँचने के रास्ते पर बैरीकेडिंग लगा दी गई है। समिति खुद वसंत पंचमी पर ठाकुर की देहरी का पूजन करना चाहती है। इससे नाराज मंदिर सेवायत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का हवाला देते हुए अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी के माध्यम से समिति अध्यक्ष व सचिव को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें देहरी पूजन न करने की अपील की है। (जास)

मुंबई में सामान्य वर्ग की महिला का मेयर की कुर्सी पर बैठना तय

राज्य ब्यूरो, मुंबई: देश की सबसे अमीर नगरपालिका मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नए मुखिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य के नगर विकास विभाग ने महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है। जिसमें मुंबई मेयर पद को ‘सामान्य महिला’ वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस फैसले के बाद अब मुंबई के ‘प्रथम नागरिक’ को कुर्सी पर किसी महिला पार्षद का बैठना तय है। यह आरक्षण लाटरी के जरिये तय किया गया, जो मुंबई के मंत्रालय में नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आरक्षण को इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिधाराओं में सरगमीं तेज हो गई हैं। 15 जनवरी 2026 को हुए चुनावों के बाद महायुति गठबंधन

- नगर विकास विभाग ने की महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के लिए आरक्षण की घोषणा
- इसके साथ ही राजनीतिक सरगमीं तेज, उद्धव की शिवसेना ने जताया कड़ा एतराज

(भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना) के पास बहुमत है। पूर्व महापौर पेडणेकर ने आरोप लगाया कि सरकार ने आरक्षण के नियमों में फेरबदल किया है। उद्धव ठाकरे गुट का मानना था कि इस बार मेयर पद अनुसूचित जनजाति (एससी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित होना चाहिए था। विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया को ‘फिक्स्ड’ बताते हुए इसका विरोध किया है।

मोदी ने 1989 के लेख से राममंदिर शिलान्यास किया याद

नई दिल्ली, आइएनएस: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 1989 में ‘अनिकेत’ उपनाम से लिखित एक लेख में अयोध्या में राममंदिर शिलान्यास समारोह को स्वतंत्र भारत में हिंदू चेतना के जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया था। यह लेख 18 नवंबर 1989 को गुजराती पत्रिका साधना के ‘अक्षर उपवन’ कालम में प्रकाशित हुआ था, जो राममंदिर शिलान्यास (नौ और दस नवंबर, 1989) की स्मृति को जीवंत करता है। यह लेख आज से दो वर्ष पूर्व 22 जनवरी, 2024 को भव्य राममंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी संतुलन को राष्ट्र प्रगति की नींव बताते हुए कहा कि धर्मग्रंथों का संदेश जीवन की दिशा बदल सकता है। इस मौके पर जैन श्वेतांबर तेरापंथ संमदाय के सर्वोच्च आचार्य महाश्रमण ने खोज, अहिंसा और करुणा का महत्व बताया।

प्रधानमंत्री उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक (आरएसएस) के सक्रिय प्रचारक थे और उन्होंने अयोध्या में शिलान्यास को 450 वर्षों की गुलामी की निशानी पर एक करारा



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● फाइल फोटो

- अयोध्या में राममंदिर शिलान्यास के बाद 18 नवंबर 1989 को लिखा था लेख

- कहा था, स्वतंत्रता के बाद पहली बार विजयश्री की ओर कदम बढ़ा रहा हिंदू

प्रहार और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की विजययात्रा के शुभारंभ के रूप में वर्णित किया था। इस लेख में उस दौर की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा गया था। तत्कालीन सरकार ने राम जन्मभूमि से संबंधित मांगों का विरोध किया था।

उस पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करने और विभिन्न चरणों में आंदोलन को बाधित करने का आरोप भी लगाया गया था। राममंदिर शिलान्यास समारोह विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित किया गया था। इसके लिए देशभर से पवित्र ईंटों (राम शिलाओं) को एकत्र किया गया था। **राममंदिर आंदोलन के दौरान आरएसएस प्रचारक के रूप में मोदी ने गुजरात में चल रहे अभियान में अहम भागीदारी की। शिलान्यास समारोह का उल्लेख करते हुए लेख में कहा गया था कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार हिंदू विजयश्री की ओर कदम बढ़ा रहा है।**

लेख में बताया गया कि कांग्रेस ने राममंदिर शिलान्यास को रोकने की पूरी कोशिश की थी। उसने अयोध्या में शिलाएं लाने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, पर कुछ हासिल नहीं हुआ।

पीएम मोदी आज केरल में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

नई दिल्ली, प्रे़र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को केरल जाएंगे। इस दौरान वे नवाचार और उद्यमिता केन्द्र की नींव रखेंगे और चुनाव वाले राज्य में चार नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मजबूत करने के प्रयासों के तहत पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। राजधानी में एक आधुनिक डाकघर का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी केरल के रेहड़ी पटरी वालों सहित एक लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण भी वितरित करेंगे। मोदी तिरुअनंतपुरम में सीएसआइआर-एनआइआइएसटी इनोवेशन, टेक्नोलाजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब की आधारशिला रखेंगे।

सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी के मामले में विधानसभा से सड़क तक सियासी महासंग्राम

तिरुअनंतपुरम, प्रे़र : केरल के सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले ने अब जांच के दायरे से निकलकर राज्य की राजनीति में बड़ा सियासी टकराव पैदा कर दिया है। गुरुवार को केरल विधानसभा के भीतर और बाहर सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित रही।

कांग्रेस-नीत यूडीएफ ने देवस्वम मंत्री वीएन वासवन के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि सोना गायब होने की जानकारी होने के बावजूद मुख्य आरोपित को दोबारा मंदिर से जुड़ा काम सौंपा गया, जो सरकार और देवस्वम बोर्ड



तिरुअनंतपुरम में गुरुवार को केरल विधानसभा के पास युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे ● प्रे़द

की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इसके जवाब में सीपीआइ(एम)-नीत एलडीएफ ने पलटवार करते हुए दावा किया कि सोना चोरी की घटनाएं कांग्रेस शासन के दौरान हुई थीं। विधानसभा में मंत्री एमबी राजेश और वी शिवनकुट्टी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपित

उन्नीकृष्णन पोट्टी की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी।

तंत्री एसआईटी हिरासत में : इसी बीच न्यायिक स्तर पर अहम घटनाक्रम में विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला तंत्री केंदरारू राजीवरू को एक दिन की एसआइटी हिरासत में भेज दिया।

पंजाब में हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

राज्य ब्यूरो, जागरण, मोहाली: पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के वादे को पूरा करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना को लांच करते हुए हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब अब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बिजली और



मोहाली में मुख्यमंत्री सेहत योजना को लांच करने के दौरान एक परिवार को स्वास्थ्य कार्ड सौंपते हुए सीएम भगवंत मान व पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। सी. लोसर्वि महिलाओं के लिए एमएफए पूजन करेगा

सभी 65 लाख परिवारों (कुल तीन करोड़ नागरिकों) को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।

भोजशाला में नामित लोग ही नमाज पढ़ सकेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय गुरुवार शाम तक उन लोगों के नाम मुहैया करा दे, जो लोग शुक्रवार को नमाज के लिए जाएंगे ताकि व्यवस्था बनाई जा सके।

गुरुवार को हिंदू फ्रंट फार जस्टिस के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआइ के 2003 के आदेश में ऐसी स्थितियों का जिक्र नहीं है जब वसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज के दिन पड़ती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को वसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट के न्यायाधीश जोयमाल्ल्या बागची ने कहा कि वसंत पंचमी की पूजा का मुहूर्त तो एक बजे का है। इस पर जैन का कहना था कि पूजा हवन आदि होता है, जो दिनभर चलता है। हर वर्ष यही होता है। तभी मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि इससे पहले भी तीन

नमाज के लिए अलग स्थान, हिंदू पक्ष दिनभर करेगा पूजा-हवन

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार धार के जिला प्रशासन ने वसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा और नमाज के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कलेक्टर प्रिथ्वि मिश्रा ने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज पूर्व परंपरा के अनुसार पूजन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट है कि दोनों समुदाय के आयोजन पृथक-पृथक स्थान पर होंगे। पूजा-अर्चना निर्विघ्न होगी। मुस्लिम समाज को अलग स्थान दिया जाएगा। ऐसे स्थान की तलाश में प्रशासन ने स्वयं



भोजशाला के गर्भगृह को विशेष रूप से सजाया गया है ● नईदुनिया

सर्वे किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से भी नक्शा लिया है। दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई। हिंदू समाज संतुष्ट है। मुस्लिम समाज से भी चर्चा हुई है। उन्हें विकल्प दिए गए हैं।

बार वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ चुकी है और दो घंटे नमाज हुई है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार और एएसआइ की

इस बार कमजोर पड़ सकता है मानसून, बरसेगी आग

अरविंद ठावर् ● जागरण

नई दिल्ली : देश में इस बार मानसून को लेकर चिंताजनक संकेत सामने आ रहे हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, जून के मध्य या इसके बाद प्रशांत महासागर में अलनीनो सक्रिय हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत में मानसूनी वर्षा पर पड़ने की आशंका है। अलनीनो की स्थिति बनने पर आमतौर पर देश में वर्षा कम होती है और गर्मी बढ़ जाती है।

आस्ट्रेलिया के मौसम विभाग (ब्यूरो आफ मेटेरोलाजी) के अनुसार, फिलहाल प्रशांत महासागर में ला-नीना की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। प्रशांत महासागर की सतह के नीचे गर्म पानी जमा हो रहा है जो आने वाले महीनों में अलनीनो को जन्म दे सकता है। मौसम



विज्ञानियों का कहना है कि फरवरी के अंत तक हालात सामान्य यानी न्यूट्रल हो सकते हैं और मार्च से मई तक यही स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन इसके बाद जून से धीरे-धीरे अलनीनो के सक्रिय होने के आसार बढ़ जाएंगे। आमतौर पर लानीना के बाद आने वाला अलनीनो ज्यादा प्रभावी माना जाता है और यही स्थिति इस साल देखने को मिल सकती है।

अलनीनो तब बनता है, जब प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय

- प्रशांत महासागर में जून के मध्य में सक्रिय हो सकता है अलनीनो
- इसके प्रभाव से भारत में ज्यादा गर्मी और कम वर्षा का खतरा
- मानसून पर असर ज्यादा जटिल और खतरनाक भी हो सकता है

क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है। इससे हवाओं की दिशा और गति बदल जाती है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत में इसका सबसे बड़ा प्रभाव दक्षिण-पश्चिम मानसून पर होता है। अलनीनो के दौरान हवा की दिशा बदल जाती है, जिससे बारिश कम होती है और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। पिछले अनुभव भी इस खतरे

भगदड़ रोकने के लिए एक समान निर्देश जारी करने से सुप्रीम इन्कार

नई दिल्ली, प्रे़र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और यात्राओं के सहित बड़ी सार्वजनिक सभाओं के दौरान भगदड़ रोकने के लिए एक समान निर्देश जारी करने से इन्कार कर दिया। एक जनहित याचिका में केंद्र सरकार को बड़ी जनसभाओं के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता तुक्बलम ग्टी वेंकटेश को केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के समक्ष इस मामले में पक्ष रखने की अनुमति दे दी। सीजेआइ ने भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे के बारे में मौलिक सवाल उठाए। कहा मुदा



- सीजेआइ ने ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे के बारे में उठाए सवाल
- शीर्ष अदालत ने कहा, यह मुद्दा राज्यों व केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से संबंधित

सार्वजनिक आयोजनों में कानून-व्यवस्था के लिए राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारी से संबंधित है। इसलिए नीति बनाने के लिए निर्देश मांगे गए हैं जिसके लिए कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के विशेषज्ञ अधिक उपयुक्त हैं।



विकसित प्रदेश की राह पर उत्तर प्रदेश

देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश

एथेनॉल उत्पादन व आपूर्ति

वर्ष 2024-25 में एथेनॉल उत्पादन 182 करोड़ लीटर



नोएडा जैसी लापरवाही से राजधानी में भी हर माह जा रही चार लोगों की जान

स्वदेश कुमार • जागरण

नई दिल्ली : नोएडा के सेक्टर 150 में बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लाट में भरे पानी में डूबकर इंजीनियर युवराज तोमर की मौत ने दिल्ली सहित एनसीआर में बुनियादी ढांचे की बढहाली और प्रशासनिक लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लाट में पानी भरा हुआ था, लेकिन आसपास बैरिकेडिंग नहीं थी। हादसे से बचाव के इंतजाम भी नदारद थे। दिल्ली में भी ऐसी लापरवाही कई स्थानों पर सामने आती है। खुले नालों और मानसून में जलजमाव में राजधानी में औसतन हर माह करीब चार लोगों की मौत होती है। दिल्ली के राजस्व विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के 24 महीनों में इस तरह के हादसों में 89 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई तो दूर

● खुले नालों और जलजमाव में डूबने से दो वर्षों में 89 से अधिक लोगों की गई जान

● कार्रवाई तो दूर, कई मामलों में आर्थिक मदद से भी वंचित रह जाते हैं पीड़ित परिवार

● करीब डेढ़ साल पहले गाजीपुर में नाले में गिरने से मां-बेटे की हो गई थी मौत



अबुल फजल एन्क्लेव मार्ग पर नाले का पानी भरा होने के कारण वाहनों की रफ्तार हुई धीमी ● विपिन शर्मा

की बात है। कई मामलों में पीड़ित परिवार तक आर्थिक मदद तक नहीं पहुँच पाती है। राजधानी में नालों और सड़कों की बहुविभागीय व्यवस्था है।

पीडब्ल्यूडी, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम और डूसिब सहित अन्य विभागों के पास इनकी जिम्मेदारी है। कई बार हादसों के समय यह बता पाना मुश्किल

हो जाता है कि किस विभाग के अधिकारी को जिम्मेदार माना जाए। इसी आड़ में विभाग और अधिकारी बच निकलते हैं। करीब डेढ़ साल पहले गाजीपुर

अबुल फजल एन्क्लेव मार्ग पर भी नोएडा जैसे हादसे का इंतजार

दिल्ली के अबुल फजल एन्क्लेव मार्ग पर नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क तक पहुँच गया है। इससे सड़क और नाले के बीच का अंतर पट गया है। यहां से वाहन चालक पानी से बचकर निकलते हैं। लेकिन, अंधेरे में यहां भी नोएडा जैसी घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह समस्या करीब एक हफ्ते से बनी हुई है। लेकिन किसी भी विभाग की तरफ से इस समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है।

में नाले में गिरने से मां-बेटे की मौत हो गई थी। इसमें डीडीए और एमसीडी एक-दूसरे का नाला बताते रहे, बाद में यह नाला एमसीडी का निकला।

न्याय दूर, आर्थिक मदद तक नहीं मिली

केस 1 06 जुलाई 2025 को उत्तर-पश्चिमी जिले के रामगढ़ गांव में पीडब्ल्यूडी के खुले नाले में गिरने से चार साल के रिजवान की मौत पर लापरवाही का हुआ था। लेकिन इसमें किसी को आरोपित नहीं बनाया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि नामजद एफआइआर नहीं होने से उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला।

केस 3 10 अगस्त 2024 को रोहिणी सेक्टर-20 स्थित डीडीए के पार्क में बने छठ घाट में वर्षा का पानी भरा हुआ था। आठ वर्षीय तरुण खेलते हुए छठ घाट के अंदर गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई थी। परिवार ने बताया पुलिस ने उस समय लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया। जांच के बाद भी संबंधित विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इस तरह के मामलों में व्यापक जांच की जरूरत होती है। इन मामलों में प्रत्यक्षदर्शी मिलना मुश्किल होता है। मिलने पर अधिकारियों के दबाव में गवाह मुकर भी जाते हैं। ऐसे में लापरवाही सिद्ध करना टेढ़ी खीर हो जाती है। यही वजह है कि अधिकांश मामलों में अधिकारी बच निकलते

दो वर्षों में हुए प्रमुख हादसे

27 जुलाई 2024 : ओल्ड राजेंद्र नगर में सड़क पर जलभराव होने से पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसा। तीन अभ्यर्थियों की मौत।

31 जुलाई 2024 : गाजीपुर में निर्माणाधीन खुले नाले में डूबने से 23 वर्षीय तनुजा और उसके 3 वर्षीय बेटे प्रियांश की मौत।

7 अक्टूबर 2024 : उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अलीपुर में पांच वर्षीय बच्चे की खुले नाले में गिरने से मौत।

5 मार्च 2025 : उत्तर-पूर्व दिल्ली में खुले नाले में गिरकर सात साल के बच्चे की मौत।

9 जुलाई 2025 : उत्तर-पश्चिम दिल्ली, महिंद्रा पार्क में चार वर्षीय बच्चे की खुले नाले में गिरने से मौत।

हैं। हालांकि अब ऐसे मामलों के लिए कानून में सजा का प्रविधान बढ़ा है। लापरवाही से मौत की आड़पीसी की धारा में जहां दो साल की सजा का प्रविधान था। अब बीएनएस की धारा में इसे सात साल कर दिया गया है। लेकिन जब तक ऐसे मामलों में सजा नहीं होती, लापरवाही पर अंकुश लगाना मुश्किल है। -मनीष भदौरिया, अधिवक्ता, कड़कड़मा कोर्ट

चश्मदीद डिलीवरी ब्याय के बयान नहीं दर्ज कर सकी एसआइटी

डिलीवरी ब्याय मुनेंद्र और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से अब तक नहीं किए गए सवाल-जवाब

युवराज को मिले न्याय

अर्पित त्रिपाठी • जागरण

ग्रेटर नोएडा : इंजीनियर युवराज को बचाने के लिए जिस डिलीवरी ब्याय ने जान की परवाह नहीं की थी, उससे अभी तक एसआइटी ने पूछताछ तक नहीं की है। जबकि उसे घटना का सबसे अहम चश्मदीद माना जा रहा है। एसआइटी तीन दिन बीतने के बाद भी बयान नहीं दर्ज कर सकी है। इस पर भी सवाल खड़े हैं। लोग दबी जुबान कह रहे हैं कि कहीं यह किसी को बचाने का प्रयास तो नहीं। एसआइटी सिर्फ प्राधिकरण, पुलिस व प्राधिकरण अधिकारियों से ही बात कर रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस-प्रशासन की इस मामले में सीधे लापरवाही सामने आई है। सिर्फ उन्हीं से बात होगी तो वह अपने बचाव में एसआइटी को सही जानकारी नहीं देंगे। सही जानकारी चश्मदीदों से ही मिलेगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मेरठ आए थे। एसआइटी के अध्यक्ष एडीजी मेरठ जोन व मंडलायुक्त मेरठ में मुख्यमंत्री के साथ ही रहे। शाम को जांच के लिए एसआइटी गौतमबुद्ध नगर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया। एसआइटी ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से सवाल-जवाब किए। सड़क पर स्थित ब्रेकर से लेकर गाड़ी गिरने तक जगह का नक्शा मार्क

3 दिन बीतने के बाद भी मुख्य चश्मदीद के बयान नहीं होने से उठ रहे हैं गंभीर सवाल

16 जनवरी को युवराज की मौत मामले में एसआइटी ने चार विभागों से मांगी थी रिपोर्ट



सेक्टर 150 में घटना स्थल पर जांच करती एसआइटी ● जागरण

कहीं छोटे अधिकारियों पर ही न फोड़ दिया जाए ठीकरा : युवराज की मौत का मामला समूचे देश में छाया है। हर कोई उसे न्याय दिलाने की बात कर रहा है। सभी चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो। लोगों की नजर एसआइटी जांच पर टिकी है। आम चर्चा है कि छोटे अधिकारियों पर ठीकरा फोड़कर कार्रवाई हो जाएगी। बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास जारी है।

देर रात पहुंचे डीसीपी-एसीपी, नहीं पहुंचा कोई और बड़ा अधिकारी : घटना वाले दिन रात करीब सवा बजे डीसीपी ग्रेटर नोएडा व एसीपी पहुंचे थे, पर तब तक बहूत देर हो चुकी थी। पुलिस व प्राधिकरण का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। जिला प्रशासन का कोई अधिकारी चार दिन तक नहीं पहुंचा।

एसआइटी को नोएडा प्राधिकरण ने सौंपी 60 पन्नों की रिपोर्ट

जासं, नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने एसआइटी को 60 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। चार विभागों से सात बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। इसमें सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से संबंधित अधिक जानकारी शामिल थी। बताया जाता है कि सेक्टर-150 में बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लाट में भरे पानी में 16 जनवरी को इंजीनियर युवराज मेहता की कार समेत डूबने के मामले में एसआइटी ने प्राधिकरण के चार विभाग सिविल, एनटीसी, नियोजन, जल खंड विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। दो दिन तक प्राधिकरण के अधिकारियों ने सौंपे बिंदुओं पर अपना जवाब तैयार किया। देर शाम अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय रिपोर्ट पर चर्चा कर संबंधित विभागों के मुखिया ने हस्ताक्षर किए। इसमें युवराज मेहता की कार डूबने से मौत के मामले में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को लिखित जवाब से एसआइटी के समक्ष प्रस्तुत किया है। बताया यहां तक जा रहा है कि एसआइटी ने इस मामले की शुरुआती फेक्ट-फाइंडिंग की जानकारी सीएम को मौखिक रूप से दे दी है।

किए गए तो वह चुपचाप कार में बैठ कर रवाना हो गई।

नमो भारत स्टेशन पर बनेंगे पाड होटल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कारिडोर के आनंद विहार स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्टेशन परिसर में आधुनिक पाड होटल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

एनसीआरटीसी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत स्टेशन के भीतर 30 पाड्स की क्षमता वाला अत्याधुनिक पाड होटल बनाया जाएगा। यह होटल विशेष रूप से उन यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो यात्रा के दौरान कुछ समय आराम करना चाहते हैं। आनंद विहार जैसे अत्यधिक व्यस्त मल्टी-माडल

● आनंद विहार स्टेशन में 30 पाड्स की क्षमता वाला बनाया जाएगा अत्याधुनिक पाड होटल

ट्रांजिट हब पर यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। मेरठ से नमो भारत ट्रेन द्वारा दिल्ली पहुंचने वाले और आगे लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने वाले यात्री स्टेशन परिसर में ही आराम कर सकेंगे। परियोजना के तहत लगभग 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को प्राप्रटी डेवलपमेंट के लिए लाइसेंस पर दिया गया है। यह क्षेत्र स्टेशन के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दो अलग-अलग स्थानों में फैला होगा। इसके अलावा यहां एक प्रीमियम डाइनिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। इसके साथ ही फूड रिटेल आउटलेट, आफिस

स्पेस, कपड़ों के शोरूम और अन्य कमर्शियल सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं, हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इसके लिए यात्रियों को कितना चार्ज देना होगा। इस पर होटल का काम पीड़ा होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन एनसीआर का प्रमुख मल्टी-माडल ट्रांजिट हब है, जहां दिल्ली मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल सीधे जुड़े हुए हैं। इसके चलते यहीं बेहद छोटे आकार के कमरों वाला पाड होटल बनाने का निर्णय लिया गया है।

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, युवती की मौत

जासं, नोएडा : फेज तीन थाना क्षेत्र में सेक्टर 71 अंडरपास के निकट बुधवार देर रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने एक बँककमी युवती गुलिफशा को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य युवक और युवती का दिल्ली में उपचार चल रहा है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। अभी मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। बरेली कोहाड़ापीर की रहने वाली गुलिफशा, दिल्ली जामिया नगर के जोहरी फार्म की रहने वाले मुर्तजा अब्बास और मथुरा धौली प्याऊ के रहने वाली अनुष्का चौधरी दोस्त हैं।



बस में लगी आग...बाल-बाल बचे लोग

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बांदा से कानपुर होते हुए दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस का बृहस्पतिवार को अचानक टायर फट गया, जिसके कारण बस में आग की लपेट निकलने लगी, जैसे-तेरे 50 यात्रियों ने बचाव गया ● सौ. वीडियो वोट

अच्छी खबर • पलवल से मानेसर तक रात का सफर होगा सुरक्षित केएमपी एक्सप्रेस-वे पर 18 करोड़ की लागत से लगेगी एलईडी लाइटें

भास्कर न्यूज़ | पलवल

केएमपी एक्सप्रेस-वे अब रात को एलईडी लाइटों से लगमगाएगा, क्योंकि 18 करोड़ की लागत से पलवल से मानेसर तक लाइटें लगेगी। एचएसआईआईडीसी ने इसका प्रोजेजल बनाकर मुख्यालय मंजूरी के लिए भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लाइटें लगने के बाद अंधेरा खत्म होने से एक्सीडेंट में कमी आएगी।

स्ट्रीट लाइटों कई वर्षों से खराब पड़ी हुई हैं: केएमपी एक्सप्रेस-वे के रखरखाव का जिम्मा एचएसआईआईडीसी के अंडर है। लेकिन कई वर्षों से एक्सप्रेस-वे की दयनीय हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। केएमपी एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करते समय कहा गया था कि इस पर सफर पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम रहेगा। वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फरिदा भर सकेंगे। लेकिन भारी भ्रकम टोल वसूलने के बावजूद एक्सप्रेस-वे की

कोट गांव में बन रहे बूचड़खाने के विरोध में लोग सीएम से मिले

पलवल | कोट गांव में बन रहे बूचड़खाने के विरोध में रावत पाल के लोग चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी से मिले। इस दौरान पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह व खेलमंत्री गौरव गौतम भी मौजूद थे। लोगों ने सीएम को बताया कि नियमों को ताक पर रख बूचड़खाने का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने डीसी से की है। डीसी ने हथीन एसडीएम को जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि बूचड़खाने के निर्माण से पहले एमिलल हस्बैंडरी व सिंचाई विभाग समेत कई विभागों से एनओसी नहीं ली गई। ग्राम पंचायत में भी एनओसी न लेकर फर्जी तरीके से एनओसी बनाई गई है। बूचड़खाने को लेकर क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है।

केंद्र ने मनरेगा का नाम परिवर्तन कर जाहिर की गोडसे की विचारधारा: अजय पटौदी

पटौदी | कांग्रेसी नेता और पूर्व प्रदेश मंत्री कैप्टन अजय यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम परिवर्तन कर अपनी गोडसे की विचारधारा को जाहिर कर दिया है। धीरे धीरे इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। अजय यादव ने गुरुवार को जाटौलीमंडी में एक पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि राम सबके हैं उनका नए नाम से विरोध नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है। यह योजना दूसरी योजना है जिससे भारत के लोगों को भला होता। भाजपा की मंशा गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी देने की योजना नहीं है।

रोजगार विभाग 2 से 6 फरवरी तक मनाएगा व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह

पटौदी | जिला रोजगार कार्यालय की ओर से डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में 2 से 6 फरवरी तक व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। रोजगार कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 02 फरवरी को व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का शुभारंभ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोलाहेड़ा व ढूँढ़ाहेड़ा से किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि मार्गदर्शन कार्यक्रम में मंडल रोजगार अधिकारी व सहायक रोजगार अधिकारी सहित अन्य विशेषज्ञों द्वार विधार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर निर्माण सम्बंधी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 02 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोलाहेड़ा व ढूँढ़ाहेड़ा में कंप्यूटर शिक्षा आदि विषयों में विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

नौकरी का झांसा देकर महिलाओं से ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार किया

गुरुग्राम | उद्योग विहार थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिलाओं से ठगी करने के मामले में पालम विहार क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को काबू किया है। आरोपी कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने दो महिलाओं के जेवररात लेकर फरार हो गया था। इससे पहले भी वह वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे जेवरात बरामदगी के लिए पूछताछ करेगी। दरअसल, उद्योग विहार थाना पुलिस में एक महिला ने शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया कि बीती चार दिसंबर को वह अपनी सहेली के साथ नौकरी की तलाश में उद्योग विहार फेस-1 क्षेत्र में गई थी।

कंपनी का स्टाफ लेकर जा रही कैब को फॉर्च्यूनर ने मारी टक्कर, 6 घायल

गुरुग्राम | गोल्फ कोर्स रोड पर कंपनी के स्टाफ को लेकर जा रही कैब में एक फॉरच्यूनर कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में छह लोग घायल हो गए, सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि फॉरच्यूनर में तीन युवक थे, जो कि पूरी तरह से नशे में मृत थे और मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सेक्टर-53 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान के आधार पर केस दर्ज करते हुए गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस को दी शिकायत में स्वरूप नगर दिल्ली निवासी निविाद कुमार ने बताया कि वह प्रीमियर पीपुल लॉजिस्टिक कंपनी में बतौर ड्राइवर कार्यरत है।

शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 53 लाख की ठगी, पुलिस कर रही जांच

भास्कर न्यूज़ | फरीदाबाद

साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर करीब 53 लाख रुपए ठग लिए। साइबर थाना सेंट्रल की पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार सेक्टर-82 निवासी ने शिकायत में कहाकि 18 नवंबर 2025 को उनका मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप से किसी ने जोड़ दिया।

इस ग्रुप में शेयर मार्केट की जानकारी दी जा रही थी। साथ ही मैसेज आ रहे थे अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते है तो प्रोग्राम को फालो करो। उन्होंने इसमें रुचि दिखाई तो उनके पास एक काल आई। काल करने वाले ने उन्हें शेयर बाजार में पैसा निवेश करने पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर करीब 52 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

बड़ौली के निर्माणाधीन बिजली घर का खेल राज्यमंत्री ने किया निरीक्षण

भास्कर न्यूज़ | पलवल

बड़ौली गांव के निर्माणाधीन बिजली घर का खेल राज्यमंत्री गौरगौतम ने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों व ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने सबसे पहले निर्माण

अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले दो तस्करों को दस-दस साल की सजा

इन तस्करों से पुलिस ने 35 पिस्टल, 6 ढेसी कट्टे और 11 मैगजीन बरामद की थीं

भास्कर न्यूज़ | पलवल

वर्ष 2022 में भारी संख्या में अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए दो तस्करों को जिला कोर्ट ने दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। इन दोषियों की निशानदेही पर पलवल पुलिस ने मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया था। यहां बनाए जाने वाले हथियार कई राज्यों में सप्लाई किए जाते थे। पुलिस ने वहां से हथियार बनाने के औजार बरामद किए थे।

पुलिस के अनुसार दस जुलाई 2022 को तत्कालीन होडल के सीआईए प्रभारी जंगेशर सिंह व हनीश खान की टीम ने सूचना मिलने पर डबचिक मोड़ पर नाकाबंदी कर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश सहित कई

वर्ष 2022 में जखीरे के साथ पकड़े गए थे

पुलिस प्रवक्ता संजय कादयान के अनुसार पुलिस ने वर्ष 2022 में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले इन दो तस्करों को पकड़ा था। इनके पास से हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के मामले में न्यायाधीश डॉ. तैयब हुसैन की अदालत ने सुनवाई करते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 25(8) के तहत बड़वानी जिले के सेंधवा निवासी किलोर सिंह व जाम सिंह को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था। आरोपियों से 35 पिस्टल व 6 ढेसी कट्टे बरामद हुए थे। इनके साथ 11 मैगजीन भी बरामद हुई थीं। आरोपियों

की पहचान एमपी के बड़वानी जिले के सेंधवा गांव निवासी किलोर सिंह व जाम सिंह के रूप में हुई थी। आरोपी इन हथियारों की हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब व राजस्थान में सप्लाई करते थे। इस कार्य में वे कई वर्षों से लगे थे। आरोपियों ने मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी।

ट्रेन का कन्फर्म टिकट दिलाने के बहाने ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भास्कर न्यूज़ | फरीदाबाद

साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने ट्रेन का कन्फर्म टिकट दिलाने के बहाने 28 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान ईश अल्लाह निवासी संगम विहार, दक्षिण दिल्ली के रूप में हुई है। इसने कॉल कर शिकायतकर्ता से पैसे खते में ट्रांसफर करने से। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार साइबर थाना सेंट्रल में सेक्टर-37 निवासी व्यक्ति ने दी शिकायत में कहाकि वह वैष्णो देवी जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराने हेतु गूगल पर सर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला, जिस पर संपर्क करने पर कॉलर ने कन्फर्म टिकट दिलाने का आश्वासन दिया। आरोपी ने टिकट के नाम पर उनसे 28 हजार रुपए अपने खते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने टिकट के संबंध में संपर्क किया तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया।

होटल में साझेदार बनाने का झांसा देकर 1.18 करोड़ हड़पे, पुलिस कर रही जांच

फरीदाबाद | जालसाजों ने सेक्टर-30 निवासी एक व्यक्ति को गोवा के मशहूर होटल में साझेदार बनाने का झांसा देकर 1.18 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपियों ने पीड़ित को होटल में निवेश करने पर अधिक मुनाफे का झांसा दिया था। साथ ही सिक्योरिटी के रूप में मैजिक पेन से हस्ताक्षर किया एक चेक दिया था। जिस पर से स्थाही कुछ दिन में उड़ गई। पीड़ित की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार सेक्टर-30 निवासी पीड़ित ने बताया कि धीरज नगर निवासी नीरज को वह बचपन से जानते हैं। नीरज ने जनवरी 2025 में रमनदीप सिंह आनंद नाम के व्यक्ति से मिलवाया। रमनदीप ने बताया कि वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं और गोवा में एंटी सरदार के नाम से उनका होटल व रेस्टोरेंट है।

नगर निगम ने 46 वार्डों में 229 क्षेत्र सभाओं का गठन किया

मोहल्ला विकास और योजनाओं में जनता निभाएगी भूमिका

भास्कर न्यूज़ | फरीदाबाद

नगर निगम ने शहर की प्रशासनिक व्यवस्था में पब्लिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा नगर नागरिक सहभागिता अधिनियम के तहत सभी 46 वार्डों में 229 क्षेत्र सभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की है। इस पहले के बाद अब मोहल्ला स्तर पर विकास कार्यों की पहचान, प्राथमिकता और निगरानी में स्थानीय लोगों की भूमिका तय होगी।

निगम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभाओं का सटन पोलिंग बूथों के अनुसार भी किया गया है। जिस पोलिंग बूथ की मतदाता सूची में जिन नागरिकों के नाम दर्ज हैं वे सभी संबंधित क्षेत्र सभा के सदस्य माने जाएंगे।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पोलिंग बूथ को विभाजित नहीं किया गया है, ताकि व्यवस्था सरल और प्रभावी बनी रहे। सभाओं को स्थानीय समस्याओं की पहचान, नागरिक जरूरतों को प्राथमिकता देने और वाई स्तर पर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दीनदयाल लाडो रक्षी योजना जैसी सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन में भी क्षेत्र सभाएं सहयोग करेंगी। स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सेवाओं में नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र सभा के लिए निगम की ओर से एक मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है जो निगम का कर्मचारी होगा।

अस्पताल के एमएस की शिकायत पर सदर थाना पुलिस में केस दर्ज

मेदांता की फर्जी वेबसाइटों से किडनी डोनेशन के नाम पर ठगी

भास्कर न्यूज़ | गुरुग्राम

गुरुग्राम स्थित मेदांता दी मेडिसिटी अस्पताल के नाम पर किडनी डोनेट करने के बदले तीन करोड़ रुपए देने का लालच देकर लोगों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मेदांता अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (एमएस) डॉ. संजय दुरानी की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक इस मामले में आरोपी महिला का पता लगाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉ. संजय दुरानी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि प्रिया संतोष नाम की एक महिला खुद को डॉक्टर बताकर लोगों के साथ ठग रही है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फर्जी वेबसाइटों और वॉट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से संपर्क करती है और किडनी डोनेशन के बदले मोटी रकम देने का झांसा देती है। दावा किया जाता है कि मेदांता अस्पताल को किडनी की सख्त जरूरत है और जो व्यक्ति अपनी किडनी दान करेगा, उसे अस्पताल की ओर से तीन करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने मेदांता अस्पताल के लोग और नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल कर एक फर्जी वेबसाइट भी बना रखी है। महिला ने खुद को अस्पताल की डॉक्टर के रूप में पेश कर फर्जी कर्मचारी आईडी (स्टाफ आईडी: 1484628डब्ल्यू) का भी उपयोग किया, ताकि लोग आसानी से झांसे में आ सकें।

जन्मदिन मना रहे लोगों पर पड़ोसियों ने ईंट-पत्थर व डंडों से किया हमला



भास्कर न्यूज़ | पटौदी

घर में बच्चे का जन्मदिन मना रहे लोगों पर पड़ोसियों ने ईंट-पत्थर व डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी डंडों से तोड़ दिया। पुलिस ने इस संबंध में पीड़िता कामनी पत्नी वरूण निवासी ततारपुर की शिकायत पर 2 महिलाओं सहित 5 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला

दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी कि वे अपने परिवार के साथ अपने बेटी पूर्वक्षी का जन्मदिन मना रही थी। घर में गाने चल रहे थे। इसी दौरान पड़ोस का रहने वाला कपिल पुत्र प्रकाश उनके घर पहुंचा और उसके ससुर सुभाष चंद्र के साथ गाली गलौच शुरू कर दी। इसके बाद वह डंडा लेकर घर में धुस आया और मारपीट शुरू कर दी। इससे पूर्व उसके घर के बाहर लगे कैमरे तोड़ दिए।

डिलीवरी बाँय को किडनेप कर ले जा रहे दो गिरफ्तार

गुरुग्राम | खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में डिलीवरी बाँय का किडनेप करके ले जा रहे दो अपहरणकर्ताओं को पुलिस की ईंआरवी ने मौके पर ही काबू कर लिया। डिलीवरी बाँय ने आरोपियों की गाड़ी से साढ़े छह लाख रुपए चोरी किए थे। जिनको वापिस नहीं देने के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल, खेड़कीदौला थाना पुलिस को एक युवक ने शिकायत देकर बताया कि वह गुडगांव में डिलीवरी बाँय का कार्य करता है। वह 21 जनवरी की शाम वापस आते समय से जयबीर व अमन तथा कुछ अन्य व्यक्ति कार से उतरे। उन्होंने युवक को गाड़ी से बाहर निकाला तथा डंडों से मारपीट की और उसे अपनी कार में डालकर अपहरण करके ले जाने लगे। इसी दौरान पुलिस की ईंआरवी टीम पहुंची और युवक को सुरक्षित छुड़ाते हुए दो आरोपियों को काबू कर लिया।

नोएडा में इंजीनियर की मौत से सबक गुरुग्राम में आधी रात हुई मॉक ड्रिल

भास्कर न्यूज़ | गुरुग्राम

नोएडा में इंजीनियर की डूबने से हुई मौत की घटना से सबक लेते हुए गुरुग्राम में रेस्क्यू टीमों ने बुधवार की आधी रात के बाद मॉक ड्रिल की। पुलिस और फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीमें रात करीब 1.20 बजे सेक्टर-53 तालाब पर पहुंची और मॉक ड्रिल शुरू की। गुरुग्राम के डीसीपी ईस्ट गौरव राजपुरोहित ने बताया कि मॉक ड्रिल प्रशस्त रही। गुरुग्राम में इस मॉक ड्रिल से सफल होने ऐसी स्थितियों में तैयारियों की जांच की। सभी टीमें समय पर पहुंचीं, सच और रेस्क्यू प्रक्रिया को अमल में लाया गया और स्थिति को ‘‘ऑल क्लियर’’ घोषित किया गया। डीसीपी ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक डूबने जैसी आपदा में फंसे तो 10-15 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच जाए।



दर्जनभर मोबाइल व तीन लाख लूट ले गए बदमाश

भास्कर न्यूज़ | नूंह

मोबाइल की दुकान में घुसे दर्जनभर लोगों ने दुकानदार से मारपीट कर लूटपाट की। हमलावर आरोपियों ने बाहर खड़ी दुकानदार की गाड़ी को भी तोड़ दिया। आरोप है कि ये नापदी व करीब 10 एफल मोबाइल भी लूटकर ले गए। पीड़ित दुकानदार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। दूसरी तरफ, पुलिस का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना मिनागवां इलाके के ढाणा रोड की है। गाम मालिका निवासी आबिद हुसैन ने एफल स्टोर के नाम से मोबाइल की दुकान खोल रखी है। बताते हैं कि देर किसी ने फोन कर उसे गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी।

प्रेरणा

जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह आजाद नहीं है।- पाइथागोरस

संपादकीय
हर बदलाव का विरोध करना उचित नहीं है

सरकार और वैज्ञानिकों के प्रयास से जीन-एडिटिंग (जीई) तकनीकी में असाधारण सफलता मिली है। इस वर्ष से कृषि में इसका इस्तेमाल एक क्रांति का आगाज हो सकता है। मानव जेनेटिक बीमारियों, जैसे सिक्ल सेल में भी आशांतीत सफलता की उम्मीद जगी है। जीन-मोडिफिकेशन (जीएम) और जीन-एडिटिंग (जीई) तकनीकियों में मौलिक अंतर यह है कि पहले में बाहरी डीएनए को लक्षित जीन में डाला जाता है, जिससे उसका मूल चरित्र ही बदल जाता है। इसलिए भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने जीएम सीड्स को प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन जीई तकनीकी में देशी क्रिस्पर विधि से की जाने वाली दो प्रक्रियाओं- एसडीएन-1 व 2 को सरकार ने वैध करार दिया है। इसमें जीन में ही मौजूद कुछ डीएनए (जैसे धान के पौधों में पानी की अवशोषण-क्षमता को कम करने वाले) को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बनाए दो नए बीज देश के किसानों के लिए हर जिले में उपलब्ध हैं। इससे 30% उत्पादन वृद्धि की आशा है और फसल पर सूखे का असर भी नहीं होगा। इसी विधि से रोगी के खून में स्टेम सेल में बदलाव करके उन सेल्स को ख़ास आकृति लेने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है। लेकिन देश में ही एक वर्ग इसे तकनीकी का विरोध करने लगा है और वह इसे जीएम जैसा मान रहा है। जबकि जीई तकनीकी पर नजर रखने के लिए भी सरकार की नियामक संस्था है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

ईश्वर से मिलने के लिए कुछ समय भीतर जाना ही पड़ेगा

जो हर जगह गुंज रहा है, उस दिव्य शक्ति, परमात्मा को समेटना ही भजन बन जाता है। भजन का सच्चा अर्थ यही है कि इसको करने वाला और सुनने वाला ध्वनि बन जाता है, मनुष्य नहीं रह जाता। जब ऐसा होता है तभी भजन का असली आनंद है। सच्चे भजन के लिए किसी अकिंस्ट्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई लोगों ने तो बिना वाद्ययंत्र के भी सुंदर भजन गा दिए। उनकी आवाज बाहर सुनाई देती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत गहरे अपने भीतर उतर चुके होते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है कि जो हर जगह दिख रहा है, वो भीतर के नेत्रों से सही देखा जाता है। चूंकि आजकल बाहर के नेत्रों के प्रयोग तो इतने अधिक वैज्ञानिक हो गए कि पूरी दुनिया देखी जा सकती है, पर दुनिया बनाने वाला देkhना हो तो भीतर ही उतरना पड़ेगा। अब तो वलैमान में जीने की सुविधा के नाम पर मेटा-चश्मों का भी प्रयोग खूब चल पड़ा। ऐसे प्रयोगों के कारण मनुष्य अत्यधिक बाहर रहने लगा, जबकि ईश्वर से मिलने के लिए कुछ समय तो भीतर जाना ही पड़ेगा। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

ब्रांड से सबक

Microsoft | अमेरिकी टेक कंपनी

2000 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट खत्म, आउट ऑफ डेट जैसी बातें चलीं, अब टेक की शीर्ष कंपनियों में

साल 2007, मशहूर अमेरिकी प्रोग्रामर और निवेशक पॉल ग्राहम ने एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था ‘माइक्रोसॉफ्ट इज डेड’। उन्होंने तर्क दिया कि गूगल और वेब-आधारित एप्स के दौर में माइक्रोसॉफ्ट अब अप्रासंगिक हो गया है। ग्राहम ने लिखा कि लोग अब माइक्रोसॉफ्ट से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल यह वह दौर था, जब टेक जगत में यह चर्चा होने लगी थी कि माइक्रोसॉफ्ट पुराने जमाने की कंपनी बन चुकी है, जो मोबाइल क्रांति में पूरी तरह से पिछड़ गई है। आंकड़े भी कुछ यही बयां करते हैं जैसे- दिसंबर 1999 में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमत 38 डॉलर थी। 2012 के अंत तक भी ये शेयर 26 से 30 डॉलर के बीच झूलते रहे। यानी 13 साल तक निवेशकों को ज़ीरो रिटर्न मिला। एक और उदाहरण है- 2000 के दशक की शुरुआत में विंडोज मोबाइल का मार्केट में दबदबा था, लेकिन 2007 में आईफोन और 2008 में एंड्रॉइड के आने के बाद 2013 आते-आते मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से भी कम रह गई। हालांकि एक समय ऐसा था कि जब तकनीक की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का मतलब ही कंप्यूटर होता था, लेकिन यह क्यों संकट में फंसा? पहिए आज ब्रांड से सबक में माइक्रोसॉफ्ट की इस कहानी को।

वर्तमान स्थिति
305 लाख करोड़ की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट

आज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, एआई, प्रोडक्टिविटी, गेमिंग और इंटरप्राइज सॉल्यूशन में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में शामिल है। उसका Azure क्लाउड प्लेटफॉर्म दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट 200 से अधिक देशों में काम कर रही है। दुनिया की 95% फॉर्च्यून 500 कंपनियां इसके क्लाउड का उपयोग करती हैं। इसके अलावा कंपनी वर्तमान में क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई पर तेजी से काम कर रही है।

सबक क्यों- 2013 में 26 डॉलर तक पहुंच गई थी माइक्रोसॉफ्ट के एक शेयर की कीमत आज 450 डॉलर से ज्यादा है मूल्य।



चार कारण, जो बने कमजोरी

- 1 मोबाइल क्रांति को नजरअंदाज करना : स्टीव जॉन्स ने जब 2007 में आईफोन लॉन्च किया, तब तत्कालीन सीईओ स्टीव बाल्मर ने उसका मजाक उड़ाया था। वे टच इंटरफेस और एप स्टोर की अहमियत नहीं समझ पाए।
- 2 इंटरनेट एक्सप्लोरर की सुस्ती : 90 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर की सुरक्षा खामियों और धीमी गति के कारण यूजर्स गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की ओर मुड़ गए, जिन्हें कंपनी वापस नहीं ला पाई।
- 3 विंडोज विस्टा की विफलता : विंडोज एक्सपी के बाद आया विंडोज विस्टा बेहद धीमा था। हार्डवेयर के साथ तालमेल में भारी दिक्कत रही। इससे ग्राहकों का भरोसा घटा।

4 कानूनी विवाद : 2000 की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप में कंपनी पर एकाधिकार को लेकर मुकदमे चले। कंपनी कानूनी चक्कर में फंस गई।

माइक्रोकंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है इसका नाम

शुरुआत : दो दोस्तों ने मिलकर रखी थी माइक्रोसॉफ्ट की नींव

माइक्रोसॉफ्ट की नींव 4 अप्रैल, 1975 को दो बचपन के दोस्तों बिल गेट्स और पॉल एलन ने रखी थी। उनका विजन था ‘हर घर और हर डेस्क पर एक कंप्यूटर’। उन्होंने अल्टेयर 8800 के लिए बेसिक (BASIC) इंटरप्रेटर बनाकर शुरुआत की, लेकिन असली सफलता 1980 के दशक में आई जब उन्होंने आईबीएम के साथ एमएस-डॉस के लिए हाथ मिलाया।

ऐसे पड़ा नाम : इसका नाम माइक्रोकंप्यूटर और सॉफ्टवेयर शब्द को मिलाकर बनाया गया है। आज माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है।

200 से अधिक देशों में काम कर रही है कंपनी।

1.45 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है सत्य नडोला ने भारत में।

20 हजार से अधिक कर्मचारी हैं भारत में कंपनी के।

95% फॉर्च्यून 500 कंपनियां इसके क्लाउड का उपयोग करती हैं।

यह तस्वीर युवा बिल गेट्स और उनके मित्र पॉल एलन की है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी।

इस तरह की वापसी

- 1 क्लाउड फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट विजन: 2014 में पद संभालते ही नडोला ने घोषणा की कि माइक्रोसॉफ्ट अब सिर्फ विंडोज कंपनी नहीं रहेगी। उन्होंने ‘Azure’ क्लाउड को प्राथमिकता दी। आज यह कंपनी की कमाई का मुख्य स्रोत है।
- 2 प्रतिद्वंद्वियों के साथ सहयोग : नडोला ने पुरानी दुश्मनी खत्म की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आईफोन व एंड्रॉइड पर उपलब्ध कराया। यहां तक कि ‘Linux’ को भी स्वीकारा, जिसे बाल्मर ने कैसस कहा था।
- 3 सार्थक अधिग्रहण : कंपनी ने लिंबडइन, गिटहब और माइक्राफ़्ट जैसे प्लेटफॉर्म को खरीदा। इससे माइक्रोसॉफ्ट को डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स का एक विशाल डेटाबेस और कम्युनिटी मिल गई।
- 4 एआई, ओपन एआई में निवेश : माइक्रोसॉफ्ट ने चैटजीपीटी वाली ओपनएआई में अरबों डॉलर निवेश किए। एआई की रेस में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में है।

गंभीर संकट : साल 2012-13 रहा कंपनी का सबसे खराब दौर

2012 में लॉन्च हुआ विंडोज-8 असफल रहा। इसी समय कंपनी ने नोकिया को खरीदने जैसा आत्मघाती फैसला लिया। उसका इनाइसट टैबलेट ‘सरफेस आर्टि’ असफल हो गया, जिससे कंपनी को उस समय 90 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान हुआ। बाद में अरबों का घाटा सहना पड़ा। इसके बाद 2013 में तत्कालीन सीईओ स्टीव बाल्मर को इस्तीफा देना पड़ा।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : गूगल, अमेजन एडब्ल्यूएस और एपल इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में शामिल हैं, जिनसे मोबाइल, क्लाउड और एआई में चुनौती मिलती है।

पीपुल भास्कर

ए.आर. रहमान

प्रसिद्ध भारतीय संगीत निर्देशक

हिंदू ज्योतिषी ने दिया था रहमान नाम, ‘मद्रास का मोजार्ट’ कहे जाते हैं, कनाडा में इनके नाम पर सड़क

साल 1989, ए.आर. रहमान करीब 22-23 साल के थे, उनका परिवार एक कठिन दौर से गुजर रहा था। पिता के निधन के वर्षों बाद भी घर की आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। खासकर उनकी छोटी बहन बहुत बीमार रहती थी। उसी दौरान, रहमान की मां, बेटी की शादी के लिए उसकी कुंडली दिखाने एक हिंदू ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने तभी रहमान के बारे में पूछा (तब उनका नाम ए.एस. दिलीप कुमार था)। कुंडली देखने के बाद ज्योतिषी ने उन्हें अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम में से कोई एक नाम रखने की सलाह दी। संयोग से उसी समय रहमान का परिवार एक सूफी संत करीमुल्लाह शाह कादरी के संपर्क में भी आया था, जिनकी दुआओं से उनकी बहन की सेहत में सुधार हुआ। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम रहमान रख लिया। बाद में मां ने उसमें अल्लाह रक्खा जोड़ दिया। इस तरह दिलीप कुमार ए.आर. रहमान बन गए। प्रसिद्धित मैगजीन टाइम ने 2004 में एक आर्टिकल में उन्हें ‘मद्रास का मोजार्ट’ की उपाधि से संबोधित किया था। दरअसल मैगजीन ने उनकी तुलना 18वीं सदी के महान ऑट्टोमन शीर्षगीतकार वोल्फगैंग अमेदियस मोजार्ट से की थी, जिन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए थे। ए.आर. रहमान अब फिल्में भी लिख रहे हैं। उन्होंने तीन फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। रहमान आज भी अधिकतर देर रात संगीत बनाते हैं, जिससे सुबह 9 से 10 बजे के बीच उठते हैं। उन्हें दक्षिण भारतीय शाकाहारी खाना अधिक पसंद है।

रोचक : एल्बम रिलीज के 20 दिन पहले से संगीत में पूरी तरह डूब जाते हैं, एक घंटे ही सोते हैं

खास : 25 की उम्र तक खुद को बेहद असफल मानते थे

- म्यूजिक में परफेक्शन के लिए एल्बम रिलीज के 20 दिन पहले से गानों में लगातार डूबे रहते हैं। इस दौरान म्यूजिकल से एक घंटा सोते हैं।
- 25 की उम्र तक खुद को बेहद असफल मानते थे। कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचा।
- गणित में काफी रुचि थी। बचपन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे।

नजरिया • त्वरित जवाबदेही तय करनी जरूरी है सिस्टम की नाकामी के नजारे आज हर तरफ नजर आ रहे हैं

कुप्रशासन

विराग गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के वकील

viraggupta@hotmail.com

33 साल पुरानी वोहरा कमेटी रिपोर्ट के निष्कर्षों को दोहराते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बिल्डर-माफिया और नौकरशाहों की सांठ-गांठ से हो रहे अवैध निर्माणों की वजह से चंडीगढ़ की सुखना झील सूख रही है। नोएडा स्पेटर्स सिटी के गड्डे में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में भी एसआईटी जांच शुरू हो गई है। गोवा के क्लब में अग्निकांड से 25 मौतों और स्वच्छतम शहर इंदौर में भी दूषित पानी से 25 मौतों के मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे सभी मामलों में सिस्टम के गुनहगार साफ दिखने के बावजूद जांच समितियों के नाम पर बढ़ रही टालमटोल संस्कृति से लोग ऊब रहे हैं। इनमें निलम्बन, बर्खास्तगी और गिरफ्तारी से आगे बढ़कर इन 4 बिंदुओं पर कार्रवाई की जरूरत है : 1. स्मार्ट सिटी : दावांस के विश्व आर्थिक फोरम में ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए यूपी सरकार ने 2.27 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नोएडा के निक्ट 29650 करोड़ की लाभात से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ की योजना बनी थी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। दंतेवाड़ा के अबूझमाड़ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 23 पुलिसियाओं की तत्काल मरम्मत के लिए फंड नहीं होने से 100 गांवों के एक लाख लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। जीडीपी में 60% योगदान देने वाले इलाकों को कवर करने वाली नगर पालिकाएं 80% से ज्यादा खर्चों के लिए सरकारी मदद पर निर्भर हैं। वेतन भुगतान, कचरा उठान, जल आपूर्ति और सड़कों के रख-रखाव के लिए पैसे नहीं हैं। नोएडा के हाईटेक एक्सपो में तकनीकी का ढोल पीटने के साथ ही आपदा प्रबंधन के मांकिड़िल का भी दिखावा होता है। लेकिन हादसे के समय ड्रोन, गोताखोर, नाव, लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित स्टफ, एक्शन प्लान : सब नदारद थे। 2. श्याचार : दिल्ली में कूड़े के तीन पहाड़ प्रदूषण के साथ ही राष्ट्रीय शर्मिंदगी का भी विषय हैं। दिल्ली नगर निगम का सालाना बजट 16530 करोड़ का है। लेकिन सीवर लाइन और नालों को ठीक करने के लिए 57 हजार करोड़ के बजट की मांग हो रही है। पार्श्व निधि के बजट को दो करोड़ सालाना किया जा रहा है। मुम्बई में 70 हजार करोड़ से अधिक के बजट वाली बीएमसी पर कब्जे के लिए 5 स्टार होटल में

पार्श्वों की मौज हो रही है। नेताओं-अफसरों के पास पानी, सफाई, सीवर लाइन के लिए विजन, प्रयास और इच्छाशक्ति- सभी का अभाव मालूम होता है। 3. ऑडिट : इंदौर में दूषित जल के खतरों के बारे में सीएजी ने 2019 में ही आगाह किया था। उसी तरह नोएडा स्पेटर्स सिटी के घोटाले के बारे में सीएजी की 2021 की रिपोर्ट में विवरण है। नेताओं और बिल्डरों की मिलीभगत से कई टुकड़ों में प्लॉटों को बांटने की वजह से सरकार को 9 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। नोएडा में बिल्डर और बैंक माफिया की मिलीभगत और प्राधिकरण के अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश पारित किए हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर नौकरशाही की चुप्पी अब पांच साल पुरानी हो गई है। दूसरी तरफ छुटभैये मामलों में पुलिस ने 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नोएडा प्राधिकरण को हादसे वाले भूखंड के स्वामित्व की जानकारी तक नहीं है ! 4. जवाबदेही : विधानसभा में दी गई जानकारी

नोएडा के हाईटेक एक्सपो में तकनीकी का ढोल पीटने के साथ ही आपदा प्रबंधन के मांकिड़िल का भी दिखावा होता है। लेकिन हादसे के समय ड्रोन, गोताखोर, नाव, लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित स्टफ, एक्शन प्लान : सब नदारद थे।

के अनुसार दिल्ली में बीते दो सालों में सीवर और नालों में ढुबने से 89 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन नोएडा मामले में सरगमों इसलिए बढ़ी, क्योंकि पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ और एयरफोर्स समेत कोई भी एजेंसी ढाई घंटे तक उस युवक को बचा नहीं सकी। अफसरों की जवाबदेही के लिए केंद्र सरकार मासिक स्कोर बोर्ड का नया सिस्टम ला रही है। भारत में अगले महिने एआई का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ऐसे में सरकार को फैसला लेना चाहिए कि भविष्य में किसी भी हादसे के बाद नई जांच समिति के गठन के बजाय एआई के माध्यम से पुराने आयोगों और समितियों की रिपोर्ट हासिल की जाएगी। इससे लंबित काम और शिकायतों का पता चलने के साथ ही अफसरों की त्वरित जवाबदेही भी फिक्स हो सकेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

ए.आर. रहमान

हिंदू ज्योतिषी ने दिया था रहमान नाम, ‘मद्रास का मोजार्ट’ कहे जाते हैं, कनाडा में इनके नाम पर सड़क

चर्चा में क्यों- हाल ही में एक बयान में पिछले 7-8 वर्षों से बॉलीवुड में पहले जितना काम न मिलने की बात कही है। इससे विवाद हो रहा है।

A. R. Rahman

27 अगस्त 2022 को कनाडा में एआर रहमान के सम्मान में उनके नाम पर सड़क का उद्घाटन किया गया था।

ए.आर. रहमान के पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने पति के वाद्ययंत्रों को किराए से देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक इस किराए से मिले पैसों से ही घर का खर्च चलता था।

जन्म : 6 जनवरी 1967, मद्रास शिक्षा : 10वीं परिवार : मां- करीमा बेगम, पत्नी-सायरा बानो (2024 में तलाक)और तीन बच्चे। संपत्ति : करीब 2000 करोड़ रुपए (विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार)

शुरुआत

दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीत से जुड़े थे पिता

ए.आर. रहमान के पिता आर.के. शेखर पार्श्व संगीत बनाते थे। जब रहमान 9 साल के थे तभी उनका निधन हो गया था। ऐसे में उन्होंने घर खर्च के लिए काम शुरू कर दिया। रहमान बताते हैं कि एक दिन प्रिंसिपल ने मां से शिकायत की। जब मां ने आर्थिक स्थिति का हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि इसे सड़कों पर ले जाकर भीख मांगो। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।

विवाह

छोटी को पसंद किया, बड़ी बहन से हुई शादी

1994 में एआर रहमान की मां बेटे के लिए लड़की ढूँढ रही थीं। वे एक दरगाह में पहुँचीं। उन्होंने एक युवती को प्रार्थना करते देखा जो उन्हें बहुत पसंद आई। वे युवती के पिता के पास पहुँचीं। उन्होंने बताया कि पहले लड़की बड़ी बहन की शादी होगी। वे सायरा थीं, जिससे बाद में शादी हुई। हालांकि 2024 में फिल्म ‘रसमदंगल मिलियनेयर’ होने की घोषणा कर चुके है।

करियर

ऑर्केस्ट्रा में गाने से लेकर ऑस्कर तक

रहमान 4 साल की उम्र से पियानो बजाने लगे थे। 11 की उम्र में वे एम.के अर्जुनन के ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गए। फिर जाकिर हुसैन आदि के साथ वर्ल्ड दूर पर जाने लगे। शुरु में टीवी विज्ञापन और जिंगल आदि के लिए संगीत बनाते थे। 1992 में मणिरत्नम की फिल्म ‘रोजा’ से पहचान मिली। 2009 में फिल्म ‘रसमदंगल मिलियनेयर’ के लिए ऑस्कर मिला।

रोचक : एल्बम रिलीज के 20 दिन पहले से संगीत में पूरी तरह डूब जाते हैं, एक घंटे ही सोते हैं

खास : 25 की उम्र तक खुद को बेहद असफल मानते थे

- म्यूजिक में परफेक्शन के लिए एल्बम रिलीज के 20 दिन पहले से गानों में लगातार डूबे रहते हैं। इस दौरान म्यूजिकल से एक घंटा सोते हैं।
- 25 की उम्र तक खुद को बेहद असफल मानते थे। कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचा।
- गणित में काफी रुचि थी। बचपन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे।

उपलब्धि : टिनिटी कॉलेज ने संगीत के लिए दी छात्रवृत्ति

- कनाडा के ओंटोरियो प्रांत के मारखाम शहर में उनके घर पर एक सड़क का नाम ए.आर. रहमान स्ट्रीट रखा गया है।
- संगीत के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए ऑस्फोर्ड के टिनिटी म्यूजिकल कॉलेज ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की थी। इससे उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा प्राप्त की है।

सम्मान : दो ऑस्कर, दो ग्रेमी, एक कुल 138 पुरस्कार

- रहमान को अब तक दो ऑस्कर, दो ग्रेमी, एक गोल्डन ग्लोब सहित सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।
- इसके अलावा उन्हें 15 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए उन्हें 18 दक्षिण भारतीय फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले हैं। रहमान ने अभी तक कुल 138 पुरस्कार जीते हैं।

बिज़नेस ब्रीफ

तीसरी तिमाही में 4.4% बढ़ी अमेरिकी जीडीपी

वॉशिंगटन | तीसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी (देश के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन) में 4.4% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को बताया कि यह वृद्धि अप्रैल-जून तिमाही के 3.8% और विभाग द्वारा अनुमानित 4.3% वृद्धि से अधिक है। 2023 की तीसरी तिमाही के बाद इतनी तेज वृद्धि नहीं हुई है।

डीएलएफ का मुनाफा 14%, आय 32% बढ़ी

मुंबई | रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे दर्ज किए हैं। शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 14% बढ़कर 1,203.36 करोड़ रहा। गिरचालन आय 32% बढ़कर 2,020.22 करोड़ रु. हो गई। तिमाही के दौरान रिफॉर्ड कलेक्शन और 3,876 करोड़ रुपए का सरप्लस कैश जनरेशन हुआ।

रैपिडो: घाटा 30% घटा, पर आय 44.2% बढ़ी

नई दिल्ली | राइट-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो की पेरेंट कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ने अपने घाटे को 30% तक कम कर लिया है। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफ़र के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का कन्सॉलिडेटेड लॉस घटकर 258 करोड़ रुपए रह गया। यह वित्त वर्ष 2023-24 में 370 करोड़ रुपए था।

भारत सबसे किफायती ऑफिस स्पेस बाजार

नई दिल्ली | अपेक्षाकृत नया बाजार होने के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से विकसित होने वाला ऑफिस स्पेस मार्केट बनकर उभरा है। वर्कप्लेस कंसल्टेंसी अल्ट्रे को ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत प्रमुख वैश्विक केंद्रों में सबसे कम किराए वाले बाजारों में से एक है। भारत और पोलैंड दुनिया के सबसे किफायती बाजारों के रूप में उभरे हैं।

शैडोफैक्स आईपीओ को 2.86 गुना सब्सक्रिप्शन

मुंबई | टेक आधारित थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ गुरुवार को अंतिम दिन 2.86 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ रिटल कैटेगरी में 2.43 गुना, क्यूआईबी (एंकर को छोड़कर) श्रेणी में 4 गुना और एनआईआई श्रेणी में 0.88 गुना सब्सक्राइब हुआ। शेयरों का आवंटन 23 जनवरी को, जबकि लिस्टिंग 28 जनवरी को होने की संभावना है।

गिफ्ट सिटी में 2030

तक 1 लाख नौकरियां

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

गुजरात में गांधीनगर के पास स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्टी सिटी) ने अपने संचालन के मात्र चार वर्षों में ही विश्व के शीर्ष वित्तीय केंद्रों में 43वां स्थान हासिल कर लिया है। गिफ्टी सिटी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2026 में वैश्विक उद्योग जनत के लीडर्स मुलाकात करके उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित किया। गिफ्टी सिटी ग्रुप सीईओ संजय कोल के मुताबिक गिफ्टी सिटी वर्तमान में 10 लाख करोड़ रुपए की बैंकिंग संपत्ति का प्रबंधन करता है। उन्होंने कहा कि गिफ्टी सिटी का लक्ष्य 2030 तक हब के कर्मचारियों की संख्या को वर्तमान 27,000 से बढ़ाकर 100,000 करने का है।

बिजनेस एंकर

16% का अच्छी सर्विस पर फोकस, 13% अपने प्रोडक्ट में स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं

एसी, फ्रिज के 67% ग्राहकों की नजर डिस्काउंट पर

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार में हर 10 में से 7 ग्राहकों की नजर कीमतों में छूट और ईएमआई जैसी सुविधाओं पर रहती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते चार महीनों में पंचे, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने में सबसे ज्यादा 67% योगदान डिस्काउंट, प्रमोशन और ईएमआई का रहा। अच्छी सर्विस पर फोकस करने वाले ग्राहक 16% और स्मार्ट फीचर्स चाहने वाले ग्राहक 13% रहे। यह रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु जैसे शहरों के डीलरों के बीच करार एक सर्वे पर आधारित है। सितंबर-दिसंबर 2025 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग में हल्का सुधार दिखा। लेकिन ऑनलाइन छूट, कीमतों में उतार-चढ़ाव और कुछ कच्चा माल महंगा होने से थोड़ी मुश्किलें भी आईं। नवंबर में पंचों की बिक्री 8.5% बढ़ी।

इंटरका • श्रम कानून, ऑपरेशनल बाधा, कमजोर रुपए से 2,581 करोड़ बढ़ा खर्च

इंडिगो: लाभ 77% घटकर 550 करोड़, 3 महीने पहले 2,582 करोड़ घाटे में थी

भास्कर बिजनेस | नई दिल्ली

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के मुनाफा काफी घट गया है। गुरुवार को जारी नतीजों के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 77.55% घटकर 5,50 करोड़ रुपए रह गया। इसके मुकाबले अक्टूबर-दिसंबर 2024 में कंपनी का मुनाफा 2,449 करोड़ रुपए रहा था। इसके बावजूद बीएसई पर कंपनी के शेयर 1% से ज्यादा बढ़त के साथ 4,914 रुपए पर बंद हुए। विश्लेषकों का कहना है कि नतीजे उम्मीद से बेहतर है।

तिमाही-दर-तिमाही आधार पर देखें तो इंडिगो के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। बीती तिमाही का मामूली मुनाफा भी इसलिए मायने रखता है कि जुलाई-सितंबर 2025 में कंपनी 2,582 करोड़ रुपए पर बंद थी। इंडिगो के पास 51,607 करोड़ रुपए की नकदी भी है, जो दिखाती है कि कंपनी पूंजी के मामले में किस कदर मजबूत स्थिति में है। हालांकि बढ़ा हुआ कर्ज और एकमुश्त खर्च के चलते आगे का मुनाफा प्रभावित हो सकता है।

नतीजा एक नजर में: कंपनी की क्षमता, यात्री, आय सब बढ़ी

कुल आय	₹23,472 करोड़	▲6.2%
ऑपरेटिंग कमाई	₹6,008 करोड़	▲0.8%
शुद्ध मुनाफा	₹5,50 करोड़	▼77.5%
यात्रियों की संख्या	₹ 3.19 करोड़	▲2.8%
कंपनी की क्षमता	₹ 4,540 करोड़	▲11.2%
(क्षमता सीट-किलोमीटर, स्रोत: कंपनी फाइलिंग)		

...फिर भी 3 अतिरिक्त खर्चों के चलते घट गया मुनाफा

₹969.3 करोड़	नए श्रम कानूनों के लागू होने से
₹577.2 करोड़	ऑपरेशनल बाधाओं के चलते
₹1,035 करोड़	रुपए की वैल्यू घटने से डॉलर में खर्च
₹2,581 करोड़	कुल अतिरिक्त खर्च हुए

कार्रवाई: केंद्र ने कोर्ट में कहा, इंडिगो को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि इंडिगो को दिसंबर की उड़ान से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को बर्खास्त करने के निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अन्य अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। इंडिगो ने टिकट रिकंडर कर दिया है, मुआवजा भी जल्द देगा।



• कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेसन हटर को हटाया जाएगा।
• हटर इंडिगो के ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के एसवीपी हैं।
• दिसंबर में उड़ानें निरस्त होने में चूक की जिम्मेदारी इन्हीं की थी।

वापसी • यूरोप पर ट्रम्प पीछे हटे, बाजार को राहत

सैंसेक्स 874 अंक उछला, पर बाद में मुनाफा वसूली

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

शेयर बाजार का रूझान गुरुवार को अचानक पलट गया। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 82,783 अंक पर पहुंच गया। इस स्तर पर निवेशकों में मुनाफा वसूली की। इससे यह बेंचमार्क इंडेक्स 398 अंक यानी 0.49% चढ़कर 82,307 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 132 अंकों (0.53%) की बढ़त लेकर 25,290 पर पहुंचा। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.3% चढ़ गया और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.13% तेजी रही। कुल 4,385 शेयरों में ट्रेडिंग हुई। 2,951 शेयर बढ़त पर 1,280 शेयर गिरावट पर बंद हुए। 69 शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन 276 शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर बंद हुए। एक एनालिसिस के मुताबिक 2026 में अब तक 600 से ज्यादा शेयर स्मॉलकैप शेयर 10% से ज्यादा नकारात्मक रिटर्न दे चुके हैं।

ट्रिगर: यूएस, यूरोप के बीच टकराव की आशंका घटी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से पीछे हटने की बात कही। उन्होंने नैटो के साथ बड़े समझौते की दिशा में प्रगति का भी संकेत दिया। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर की आशंका कम हुई और वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल बना।

आगे क्या: उतार-चढ़ाव बने रहने के संकेत

निफ्टी 25,435 के ऊंचे स्तर से फिसलकर 25,168 तक गिरा। फिर भी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 200-दिवसीय औसत से ऊपर बंद हुआ। इंडिया विक्स 13.35 पर रहा। उतार-चढ़ाव रह सकता है। – रुपक डे, टेक्निकल एनालिस्ट, एलकेबी सिक्योरिटीज

जीईआई • रिफाइनरी, कपड़ा उद्योग शामिल

केंद्र ने तय किए 208 उद्योगों के लिए उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग तंत्र के जरिये ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने पेट्रोलियम रिफाइनरियों और टेक्सटाइल सहित 208 उद्योगों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) के लक्ष्य तय कर दिए हैं। इससे भारतीय कार्बन बाजार का विस्तार 490 बाध्य स्थाओं तक हो गया है। सरकार ने अक्टूबर 2025 में एल्युमीनियम, सीमेंट और पल्प एंड पेपर जैसे 282 क्षेत्रों के लिए जीईआई लक्ष्य तय किए थे। अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने वाली

सीसीटीएस देती है क्रेडिट

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट प्रदान करती है। इसे कार्बन पर मूल्य निर्धारित करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और भारत को अपने नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्य तय करती है।

कंपनियों को क्रेडिट मिलते हैं, जबकि लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को अनुपातन के लिए क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं।

ट्रम्प राज • औसत अमेरिकी से करीब 16,000 गुना हो गई एसेट

ट्रम्प ग्रोथ: 1 साल में 13 हजार करोड़ बढ़ी संपत्ति, पुणे वर्ल्ड सेंटर से आय, क्रिप्टो का बड़ा योगदान

• The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यक्तिगत संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। जनवरी 2025 में सप्ता में लौटने के बाद से साल भर में ही ट्रम्प की कुल संपत्ति करीब 13 हजार करोड़ रुपए बढ़ी है। एक औसत अमेरिकी परिवार की तुलना में ट्रम्प की संपत्ति 16,000 गुना ज्यादा है। हालांकि ये अनुमान भी ट्रम्प की कुल आय को पूरी तरह नहीं दर्शाता है क्योंकि आय के कई स्रोत स्पष्ट नहीं हैं। विदेश नीतियों से खुद के बिजनेस को फायदा: वियतनाम पर पहले 46% टैरिफ लगाया। हनोई के पास ट्रम्प

2 लाख करोड़ रु. की इवेंट्री

दुनिया में तेजी से घट रही है शराब की मांग

एजेंसी | तंदन

ग्लोबल स्पिरिट्स इंडस्ट्री कोविड काल के 'बूम' के बाद भारी मंदी के दौर में है। डियाजियो और पेनॉड रिकार्ड सहित दुनिया की पांच सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों के पास वर्तमान में करीब 2 लाख करोड़ की शराब का स्टॉक जमा हो चुका है। एफटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इवेंट्री पिछले 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। दरअसल, साल 2021-22 में कंपनियों ने भविष्य की मांग का गलत अनुमान लगाकर रिकॉर्ड उत्पादन किया, लेकिन महंगाई ने उपभोक्ताओं की जेब ढीली कर दी। अब सरप्लस स्टॉक कंपनियों के लिए कर्ज का बोझ बढ़ा रहा है। हालात सुधारने के लिए कंपनियां 'प्राइस वॉर' पर उतर आई हैं और प्रीमियम ब्रांड्स की बोतलों की कीमतों में 22% तक कटौती करने को मजबूर हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि संकेत के प्रति जागरूकता और वजन घटाने वाली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल ने लोगों की शराब पीने की इच्छा कम कर दी है।

एअर इंडिया को 15 हजार

करोड़ घाटे की आशंका

मुंबई | पिछले साल अहमदाबाद में विमान हादसे और हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण एअर इंडिया को रिकॉर्ड सालाना घाटा होने की आशंका है। कंपनी से जुड़े लोगों के मुताबिक, टाटा ग्रुप की यह एयरलाइन, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष 2025-26 में कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का घाटा उठाएगी। पाकिस्तान द्वारा भारतीय कंपनियों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से भी एअर इंडिया की आय प्रभावित हुई है। यह उलटफेर है क्योंकि बीते साल जून में डौमलाइनर हादसे से पहले एअर इंडिया मुनाफे में आने वाली थी। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टोफर के दस्तावेजों से पता चलता है कि एअर इंडिया को बीते तीन वर्षों में 32,210 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस बीच टाटा ग्रुप ने कैम्पबेल लिक्विन की जगह नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है।

भारत को बताया डेड इकोनॉमी, यहां से अरबों की कमाई



ट्रम्प ने सऊदी, ओमान और भारत में फ्रैले प्रोजेक्ट की लाइसेंसिंग डील से करीब 210 करोड़ रुपए कमाए। इनमें पुणे स्थित ट्रम्प वर्ल्ड सेंटर भी है। लॉन्ग टर्म में 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है। अपने पहले टर्म में, ट्रम्प ने आतंकवाद विरोधी सहयोग के नाम पर पाक पर धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन आज, करीब 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो-संबंधित सौदे की खबरों के बाद पाकिस्तान को फिर से ट्रम्प का समर्थन मिल गया है।

ऑर्गनाइजेशन की 14 हजार करोड़ की गैलफ परियोजना को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद टैरिफ घटाकर 20% कर दिया। ट्रम्प से जुड़ी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनंशियल और मीम कॉइन वेंचर ने बीते साल कम से कम 80

नियम • बीईई मानकों में छूट हटाने की तैयारी

रियायत हटने से छोटी पेट्रोल कारों के दाम बढ़ सकते हैं

दीपक परेल | नई दिल्ली

आगामी महीनों में छोटी-हल्की

पेट्रोल कारों के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) कैफे-3 नियम बदलने की तैयारी कर रहा है। सितंबर 2025 के मसौदे में 909 किलो से कम वजन वाली पेट्रोल कारों को खास रियायत दी गई थी। लेकिन अब बीईई ये विशेष प्रावधान हटाने पर विचार कर रहा है। छोटी और हल्की कारों के लिए कैफे-3 नियमों में छूट विवाद का विषय रहा है। कुछ कंपनियों का कहना है कि मौजूदा नियमों से सिर्फ एक कंपनी (मारुति सुजुकी इंडिया) को ज्यादा फायदा होता है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी का तर्क है कि अगर छूट खत्म हुई तो छोटी और सस्ती कारों का भविष्य खरों में पड़ सकता है। नए नियम 2027-28 से लागू होंगे।

मंथन: अब राहत के नए

फॉर्मूले पर हो रहा विचार • अभी हल्की कारों को प्रति किमी उत्सर्जन लक्ष्य में 3 ग्राम तक की राहत है। लागत कम बैठती है। • बड़ी कारें, एसयूवी बनाने वाली कंपनियां छोटी कारों पर इस छूट का विरोध करती रही हैं। • बीईई वजन आधारित फॉर्मूले पर विचार कर रहा। छोटी कारों को नए तरीके से राहत दी जा सकती है।

ग्रीन बिजनेस एक छत के नीचे

रिलायंस की 16 सहायक कंपनियों का हुआ विलय

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने अपने क्लीन एनर्जी पेट्रोफिलियो को मजबूती देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपनी 16 सहायक कंपनियों का रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड (आरएनईएल) में विलय कर दिया है। यह एकीकरण 21 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते व्यवसायों को एक ही मैनेजमेंट के तहत लाना है। कंपनी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रक्रिया पूरी की है। रिलायंस को क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के संचालन में आसानी होगी।

गोल्ड लोन ग्रोथ 40%, 4 लाख करोड़ पहुंच रहा कुल कर्ज

मुंबई | गोल्ड लोन एनबीएफसी के प्रबंधन के तहत एयूएम वित्त वर्ष 2027 तक 4 लाख करोड़ पर होने का अनुमान है। इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के बीच इसमें 40% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिल सकती है,

जो कि 2023-2025 के दौरान रही 27% की वृद्धि से अधिक है। गोल्ड लोन एनबीएफसी का प्रति शाखा औसत बिजनेस बीते दो वित्त वर्षों में 40% बढ़ा।

ये ट्रेड रुकने वाला नहीं है, क्योंकि • चालू वित्त वर्ष के

पहले 9 माह में सोने के दाम 68% बढ़े। गिरवी रखे सोने की वैल्यू बढ़ने से कंपनियां ज्यादा कर्ज दे पाती हैं।

• 1 अप्रैल से लागू होने वाले लोन-टू-वैल्यू मानदंडों के सरल होने से कर्ज तेजी से बढ़ेगा।

कंज्यूमर ट्रेंड्स • 5.5 लाख करोड़ के लोन बाजार में जोखिम बढ़ा

देश में 31-40 वर्ष की उम्र में लोन लेने वाले सबसे ज्यादा 8.20 करोड़

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय लोन मार्केट में बड़ा बदलाव दिख रहा है। नवंबर 2025 तक 'न्यू-टू-क्रेडिट' (एनटीसी) यानी पहली बार लोन लेने वालों में 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 35.5% पहुंच गई। इस वर्ग में सालाना आधार पर प्रति उधारकर्ता औसत कर्ज राशि 18% बढ़ी है। चिंता की बात यह है कि 30 वर्ष से कम उम्र के उधारकर्ताओं में लोन चुकाने में देरी अन्य समूहों से कहीं अधिक है। युवाओं में शुरुआती चूक (31-90 दिन) ज्यादा है, वहीं 60+ उम्र के लोगों में देर से होने वाली चूक (91-180 दिन) की चुनौती बढ़ रही है। क्रिफ की क्रेडिट इन्साइट रिपोर्ट में बताया गया है कि अब समय आ गया है कि कर्ज देने वाली संस्थाएं केवल ग्रोथ पर नहीं, बल्कि कर्ज की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें।

देश में 25 वर्ष से कम उम्र वाले कर्जदाता 2.7 करोड़					
आयु वर्ग	उधारकर्ता (करोड़)	POS	POS वृद्धि	POS हिस्सेदारी	औसत कर्ज प्रति व्यक्ति (रुपए)
25 से कम	2.7	5.0	17.1%	7.6%	1,85,315
26-30	3.9	12.6	19.0%	19.0%	3,20,621
31-40	8.2	46.6	10.7%	29.4%	5,65,290
41-50	6.7	46.5	9.2%	29.3%	6,98,701
51-60	4.4	30.1	9.0%	19.0%	6,91,480
60+	3.0	17.8	7.7%	11.2%	5,87,191
कुल	28.9	158.6	8.6%	100%	5,48,788

नोट: POS: पोस्टफॉलोव आउटस्टैंडिंग साइज (लाख करोड़ रु.), स्रोत: क्रिफ

कंज्यूमर ड्यूरेबल, पर्सनल, क्रेडिट कार्ड कर्ज बढ़ रहा

• नवंबर 2025 तक भारत में कुल 1,988.8 लाख सक्रिय लोन खाते हैं, सालाना वृद्धि 11% है।
• 31-40 साल के ग्रुप के पास 32.2% सक्रिय लोन खाते हैं। कुल खाते 515 लाख हैं।
• 25 से कम उम्र के युवाओं के पास 315.8 लाख और 26-30

वर्ष वालों के पास 210 लाख सक्रिय लोन खाते हैं।
• 30 वर्ष से कम और 31-40 वर्ष के लोग मुख्य रूप से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन को प्राथमिकता दे रहे हैं।

रणनीति • विज्ञापन से इतर आय पर फोकस

यूट्यूब: शॉर्ट्स में प्रोडक्ट लिंक करेगा, ब्रांड साझेदारी भी बढ़ाएगा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

यूट्यूब अब विज्ञापन से इतर कमाई बढ़ाने पर फोकस करेगी। सीईओ नील मोहन ने गुरुवार को कहा कि इसके लिए शॉपिंग और सीधी आय के साधन



मजबूत किए जा रहे हैं। शॉर्ट्स में प्रोडक्ट लिंक करना और ब्रांड के साथ साझेदारी बढ़ाना इनमें शामिल

शॉर्ट्स से अब रोजाना 200

अरब व्यूज जनरेट हो रहे दिखेंबर में 'आर्क' बटन से 2 करोड़ व्यूजर्स ने क्रिएटर्स से सवाल किए। ऑटो-डबिंग टूल से 60 लाख व्यूजर्स ने 10 मिनट से ज्यादा कंटेंट देखा। शॉर्ट्स से रोज 200 अरब व्यूज जनरेट होते हैं।

है। नए फीचर्स से क्रिएटर्स वीडियो में स्पॉन्सर क्रिएटिव्स को जल्द के हिसाब से स्वीप कर सकेंगे।

फोनपे आईपीओ • पूरी तरह ऑफर फॉर सेल

वॉलमार्ट-टाइगर ग्लोबल फोनपे में 10,000 करोड़ रु. के शेयर बेचेंगे

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

फोनपे के शेयरधारक वालमार्ट, टाइगर ग्लोबल, और माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल फाइनेंस, कंपनी के आगामी आईपीओ के जरिये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। फिफ्टेक फर्म के अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार ये हिस्सेदारी करीब 10,115 करोड़ रुपए मूल्य की है। इस आईपीओ में प्रमोटर डब्ल्यूएम डिजिटल कॉमर्स होल्डिंग्स सहित

पहली छमाही में फोनपे

का घाटा 20% बढ़ा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में फोन पे का शुद्ध घाटा 1,444 करोड़ रुपए हो गया। ये बीते वित्त वर्ष की समाप्त अवधि के 1,203 करोड़ के घाटे से 20% ज्यादा है।

मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 5.06 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है।

रणनीति • ₹1.91 लाख करोड़ सब्सिडी पर लगाम

डिजिटल किसान आईडी से घटेगा यूरिया सब्सिडी का बढ़ता बोझ

दीपक परेल | नई दिल्ली

सरकार यूरिया सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए डिजिटल किसान आईडी का सहारा लेने की तैयारी में है। सरकार एग्री स्ट्रेक प्लेटफॉर्म के जरिये यूरिया बिक्री को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने पर विचार कर रही है। यह योजना अभी पायलट स्तर पर है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी 1.91 लाख करोड़ तक पहुंचने का

सात जिलों से शुरुआत

पहले चरण में उन सात जिलों को चुना गया है जहां किसान आईडी बड़ी संख्या में बन चुकी है। यहां केवल सत्यापित आईडी वाले किसान या भूमि मालिक ही यूरिया खरीद सकेंगे। बाद में जमीन और फसल के आधार पर कोटा बनेगा।

अनुमान है, जबकि बजट अनुमान 1.68 लाख करोड़ का था।

फैसला • 100 करोड़ जमा करने पर हटेगी पाबंदी

ट्रेडिंग गुरु अवधूत साठे को राहत; 546 करोड़ रु. की जब्ती पर रोक

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

शेयर बाजार के चर्चित ट्रेडिंग गुरु अवधूत साठे और उनकी एंकेडमी को सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सेट) से बंदी लगा मिली है। ट्रिब्यूनल ने सेबी द्वारा साठे की 546 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने और बैंक खाते फ्रीज करने के पुराने आदेश को स्थगित किया है।

से